www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 130 | जौनपुर बुधवार, 24 दिसम्बर 2025 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

सीमा से सटे 5 जिलों पर फोकस, दूसरे चरण में पूछा जाएगा सवाल

नई दिल्ली, (एजेंसी)। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के पहले चरण के दौरान मतदाताओं द्वारा प्रस्तुत गणना प्रपत्रों में विसंगतियों के मामलों की सुनवाई के लिए चुनाव आयोग (ईसी) तैयार है। इस दौरान आयोग का ध्यान पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों पर केंद्रित है, जहां तार्किक विसंगतियां बहुतायत मात्रा में पाई जा रही हैं। 16 दिसंबर को चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित किया था, जिसमें 58 लाख से अधिक नाम हटाए जाने के बाद मतदाताओं की संख्या 7.66 करोड़ से घटकर 7.08 करोड़ हो गई थी। चुनाव आयोग के अनुसार, माता–पिता की आयु में 15 वर्ष से कम का अंतर दक्षिण 24 परगना (1,39,702) में सबसे अधिक है, इसके बाद उत्तर 24 परगना (92,951), नादिया (64,114), मुर्शिदाबाद (63,148) और मालदा (44,920) का स्थान आता है। इसी प्रकार, जिन मामलों में माता–पिता की आयु 50 वर्ष से अधिक है, उनमें भी सबसे अधिक दक्षिण 24 परगना (1,09,567) में है, इसके बाद मुर्शिदाबाद (88,014), उत्तर 24 परगना (77,476), मालदा (54,704) और नादिया (49,410) का स्थान आता है। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया हमें उम्मीद है कि दक्षिण और उत्तर 24 परगना, मुर्शिदाबाद, मालदा, नादिया और उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर जैसे जिलों में सुनवाई के मामले बढ़ेंगे।

सीएम पद की अटकलों के बीच डीके शिवकुमार का दिल्ली दौरा

कर्नाटक, (एजेंसी)। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंगलवार को दिल्ली यात्रा के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि यह यात्रा केवल सिंचाई और शहरी विकास जैसे राज्य के मुद्दों पर केंद्रीय मंत्रियों से मिलने के लिए थी और उन्होंने किसी भी राजनीतिक एजेंडे से इनकार किया। उन्होंने कहा कि मैं यहां किसी राजनीति के लिए नहीं आया हूंय मैं केवल अपने राज्य, सिंचाई और शहरी विकास के संबंध में केंद्रीय मंत्रियों से मिलने आया हूं। मैं अभी अन्य राजनीतिक मुद्दों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। उन्होंने अन्य राजनीतिक मामलों पर टिप्पणी करने से परहेज किया। यह सब मुख्यमंत्री पद के रोटेशन को लेकर चल रही अटकलों के बीच हो रहा है। सरकार के कार्यकाल का आधा समय पूरा होने के बाद ढाई साल के सत्ता–साझाकरण समझौते की अफवाहें फिर से जोर पकड़ रही हैं। शिवकुमार ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड रोजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम की आलोचना करते हुए।

अवकाश सूचना

सभी पाठकों को सूचित किया जाता है कि क्रिसमस डे के अवसर पर्व पर कार्यालय व प्रेस में अवकाश रहेगा।

अतः अगला अंक समय प्रकाशित होगा।

प्रबन्धक

सीएम योगी ने किसानों, एफपीओ, कृषि वैज्ञानिकों को किया सम्मानित

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जयंती पर आयोजित शकिसान सम्मान दिवसश में शामिल हुए। सीएम योगी ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस पर विधान भवन प्रांगण स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। सीएम योगी ने पांच किसानों को ट्रैक्टर की चाबी भी दी। साथ ही 25 ट्रैक्टरों को झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही किसानों, वैज्ञानिकों, एफपीओ आदि को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर उन्होंने चौधरी चरण सिंह के वक्तव्य का जिक्र करते हुए कहा कि वे हमेशा देश, गांव व किसान के हित में काम करते थे। वे कहते थे कि जब तक किसान गरीब रहेगा, भारत अमीर नहीं हो सकता। ग्रामीण भारत ही असली भारत है। भारत की समृद्धि का मार्ग देश के खेत व खलिहान से होकर गुजरता है। जागरूक जनशक्ति ही सफल लोकतंत्र का आधार है। यूपी सरकार में उन्हें जब मौका मिला तो भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने जालौन की प्रवेशिका, शाहजहांपुर से उधम सिंह, फतेहपुर से मुकेश, मुजफ्फरनगर से श्रीपाल और लखीमपुर खीरी से जमाइफ खान को ट्रैक्टर की चाबी प्रदान की। सीएम योगी ने विभिन्न फसलों के उत्कृष्ट उत्पादन के लिए किसानों को सम्मानित भी किया। इसके साथ ही उन्होंने सभी को एक–एक लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि, प्रशस्ति पत्र और अंगवस्त्र भेंट किए। उन्होंने धान उत्पादन के लिए कमलनाथ, गेहूं उत्पादन के लिए बिजेंद्र कुमार सिंह, चना उत्पादन के लिए आशीष तिवारी, मटर उत्पादन के लिए रामकिशुन, सरसों उत्पादन के लिए हीरालाल, अरहर उत्पादन के लिए रणधीर सिंह और ज्वार उत्पादन के लिए अमरेश कुमार को एक लाख रुपये, प्रशस्ति पत्र और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। इसके अलावा किसान सम्मान दिवस पर विशिष्ट महिला किसान का पुरस्कार संध्या सिंह को दिया गया। उन्हें 75 हजार रुपए, अंगवस्त्र और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया। वहीं एफपीओ में विकास कुमार सिंह (जया सीड्स कंपनी लिमिटेड, वाराणसी) को एक लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र व अंगवस्त्र भेंट किया गया। कुलदीप मिश्र (गोंडा) को बीज विकास निगम में सर्वाधिक बीज सप्लाई करने वाले एफपीओ के लिए सम्मानित किया गया।

सभी मोर्चों पर दिल्ली की पुरानी समस्याओं को सुलझाना : सीएम रेखा गुप्ता

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई के बीच, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को कहा कि सरकार विरासत में मिली समस्याओं को चुनौतियों के तौर पर ले रही है और हर मोर्चे पर उन्हें मजबूती से हल कर रही है। एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो मैसेज में सीएम गुप्ता ने कहा, ष्दिल्ली को अब साफ प्लान, लगातार कोशिशें और ठोस नतीजे मिल रहे हैं। हमारी सरकार एक लगातार विकास करने वाली दिल्ली, एक साफ और सुंदर दिल्ली बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार पिछली सरकारों से मिली समस्याओं से निपट रही है, जो इन चुनौतियों का सामना करने में नाकाम रही थीं।मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी एक दिन बाद आई, जब उन्होंने एक रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की और दोहराया कि सरकार प्रदूषण फैलाने वाले सभी स्रोतों के खिलाफ जीरो–टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएगी। सोमवार को हुई मीटिंग में लिए गए मुख्य फैसलों में शामिल थेरू बिना किसी छूट के पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल दिल्ली–एनसीआर नियमों को सख्ती से लागू करनाय दिल्ली–एनसीआर में पूल्ड और शेयर्ड इलेक्ट्रिक बस सेवाओं की संभावना तलाशनाय ई–रिक्शा के लिए नए दिशानिर्देश जारी करना और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बस रूट को तर्कसंगत बनाना। मीटिंग में पर्यावरण और परिवहन विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति , लोक निर्माण विभाग और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के साथ–साथ पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद थे।

अरावली का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा संरक्षित क्षेत्र में ही रहेगा : भूपेंद्र यादव

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने रविवार को अरावली पहाड़ियों के संरक्षण में ढील दिए जाने के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि अरावली का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा संरक्षित क्षेत्र में ही रहेगा। खनन की अनुमति केवल सीमित क्षेत्र में ही दी जाएगी, जो सुप्रीम कोर्ट की कड़ी निगरानी के अधीन होगा। कोई छूट नहीं दी गई अरावली पहाड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश को लेकर उठे विवाद पर यादव ने कहा, ष्अरावली के मामले में कोई छूट नहीं दी गई है। अरावली पर्वतमाला चार राज्यों – दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात – में फैली हुई है। इस संबंध में एक याचिका 1985 से अदालत में लंबित है।ष अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने कहा, श्भ्रम फैलाना बंद करें! अरावली के कुल 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मात्र

0.19 प्रतिशत हिस्से में ही खनन की पात्रता हो सकती है। बाकी पूरी अरावली संरक्षित और सुरक्षित है।श्विवादित ष्100 मीटरष वाली परिभाषा को स्पष्ट करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गलत जानकारी फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा, ष्कुछ यूट्यूब चौनल 100 मीटर की सीमा को शीर्ष 100 मीटर के रूप में गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, जो सही नहीं है। 100 मीटर से तात्पर्य पहाड़ी के शीर्ष से नीचे तक के फैलाव से है, और दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच का अंतर भी अरावली श्रृंखला का हिस्सा माना जाएगा। इस परिभाषा के अनुसार, 90 प्रतिशत क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है।ष्यादव ने सुंदरवन बाघ अभ्यारण्य में पत्रकारों से कहा कि खनन पर कड़ा नियंत्रण बना रहेगा। उन्होंने कहा, ष्मेरी बात याद रखिए, अरावली के कुल क्षेत्रफल में से केवल लगभग 217 वर्ग किलोमीटर ही खनन के लिए योग्य है।

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की

नई दिल्ली, (एजेंसी)। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित चौधरी चरण सिंह की जयंती पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र का नेतृत्व करते हुए दिग्गज नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की और किसानों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज के वंचित वर्गों के प्रति उनके आजीवन समर्पण को याद किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए एक पोस्ट में, प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें एक महान राजनेता बताया, जिनका राष्ट्र निर्माण में योगदान अविस्मरणीय है। प्रधानमंत्री ने लिखा, ष्पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर हार्दिक श्रद्धांजलि। उन्होंने अपना जीवन समाज के वंचित वर्गों के कल्याण के साथ–साथ कृषि की प्रगति और किसानों की समृद्धि के लिए समर्पित किया। एक कृतज्ञ राष्ट्र राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को कभी नहीं भूल सकता।नेताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पूर्व प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि ने गरीबों के कल्याण और कृषि क्षेत्र के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को प्राथमिकता देने में भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री की भूमिका को भी रेखांकित किया।भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चौधरी चरण सिंह की किसानों और गरीबों के प्रति आजीवन प्रतिबद्धता को याद करते हुए। कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए उनका संघर्ष पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। "पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर, जो किसानों के कल्याण के लिए हमेशा समर्पित रहे, मैं उन्हें अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। श्री चौधरी जी ने अपना पूरा जीवन देश के किसानों, गरीबों और वंचितों के हितों की रक्षा और उन्हें सशक्त बनाने में समर्पित कर दिया। आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए उनका संघर्ष और किसानों के कल्याण और कृषि विकास के लिए उनके प्रयास हमें सदा प्रेरित करते रहेंगे," नड्डा ने कहा।इसके अलावा, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दिवंगत प्रधानमंत्री को याद करते हुए उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में वर्णित किया।

जेपी नड्डा की अध्यक्षता में भाजपा सांसदों की होगी पहली बैठक

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसदों की पहली बैठक मंगलवार को होगी, जिसकी अध्यक्षता भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन करेंगे। यह बैठक मंगलवार को रात 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। भाजपा सूत्रों के अनुसार, बैठक में संसद खेल महोत्सव के सफल आयोजन की रणनीति को अंतिम रूप देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पार्टी सूत्रों ने बताया, ष्बैठक का मुख्य उद्देश्य संसद खेल महोत्सव के सफल आयोजन को सुनिश्चित करने की रणनीति को अंतिम रूप देना है। आयोजन से संबंधित समन्वय और तैयारियों पर विस्तृत चर्चा होगी। बैठक के दौरान भाजपा कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का पार्टी के सांसदों से औपचारिक परिचय कराया जाएगा। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया भी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन के साथ बैठक में शामिल होंगे। सभी भाजपा सांसदों के बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री 25 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संसद खेल महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे। आज की बैठक में समापन समारोह से पहले की तैयारियों और व्यवस्थाओं की समीक्षा और चर्चा भी की जाएगी। नबीन आज बिहार में विभिन्न पार्टी कार्यक्रमों में भाग लेने और कार्यकर्ताओं तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए आ रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने के बाद यह उनकी पहली बिहार यात्रा है। 45 वर्ष की आयु में नबीन पार्टी में अब तक चुने गए सबसे युवा कार्यकारी अध्यक्ष हैं।

वे बिहार मंत्रिमंडल में सड़क निर्माण मंत्री भी हैं। भाजपा ने 14 दिसंबर को नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया, जो पार्टी के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण पीढ़ीगत बदलाव का प्रतीक है। भाजपा सूत्रों के अनुसार, उनका चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन से जुड़ा हुआ है। भाजपा नेतृत्व का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि 2047 तक, जब भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाए, पार्टी के पास एक परिपक्व और अनुभवी नेतृत्व हो। इसी उद्देश्य से पार्टी ने युवा नेताओं को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया है। इस कदम को पार्टी की संगठनात्मक संरचना को मजबूत करने और विभिन्न राज्यों की प्रतिभाओं को पहचानने के लिए एक रणनीतिक निर्णय के रूप में देखा जा रहा है।

अलगाववादी नेताओं जैसी हो गई है राहुल गांधी की बुद्धि : केशव प्रसाद मौर्य

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विदेशी धरती पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा भारत की चुनावी व्यवस्था पर सवाल उठाए जाने की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की बुद्धि अब देशविरोधी और अलगाववादी नेताओं जैसी हो गई है। केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि भारत की संवैधानिक संस्थाओं को विदेशी भूमि से निशाना बनाना सत्ता से दूर होने की विचलित अवस्था का परिणाम है। इस जन्म में प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं मिलने की हताशा और निराशा में दिया गया राहुल गांधी का यह बयान निंदनीय है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और उनसे तत्काल माफी मांगने की मांग करते हैं। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि कांग्रेस को बूथ स्तर पर, विधानसभा चुनावों और निकाय चुनावों में मेहनत करनी चाहिए। भाजपा के नेता मेहनत करेंगेतो टीएमसी, सपा और कांग्रेस नहीं जीत पाएगी। कमल का फूल खिलेगा और 2047 तक देश व प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि जिन प्रदेशों में नहीं है, वहां भी बनेगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव की बुद्धि खराब हो गई है। बिहार चुनाव के बाद से वे संतुलन खो चुके हैं और मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं। बौखलाहट में दिए गए बयान और लगाए गए पोस्टर हताशा दिखाते हैं। गुंडा माफिया के खिलाफ कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई होगी।

भारत विरोधी ताकतों को एकजुट करने के लिए जाते हैं विदेश : राहुल गांधी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि भारत का संस्थागत ढांचा पूरी तरह से खतरे में है और इसका इस्तेमाल सत्ताधारी भाजपा के पक्ष में हथियार के तौर पर किया जा रहा है। बर्लिन के हर्टी स्कूल में गांधी के भाषण पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता पर विदेशों में भारत का अपमान करने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने मंगलवार को जर्मनी में हुई एक बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयानों पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता विदेशी धरती पर अराजकता, अशांति और भारत की विफलता का माहौल बना रहे हैं। राहुल गांधी की टिप्पणियों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भंडारी ने ऐसे बयानों के पीछे के इरादे पर सवाल उठाया और कांग्रेस पर भारत–विरोधी मानसिकता रखने का आरोप लगाया।

कांग्रेस नेता के बयान का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए भंडारी ने लिखा, क्या भारत से प्यार करने वाला व्यक्ति भारत की विफलता चाह सकता है? जर्मनी में राहुल गांधी कहते हैं कि उन्हें लगता हैरू लोग आपस में लड़ेंगे, भारत विफल होगा और अशांति फैलेगी। भारतीय राज्य से लड़ने से लेकर अराजकता की धमकी तक। भाजपा प्रवक्ता ने आगे आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारत के लोकतांत्रिक संस्थानों और प्रगति के विरोधी तत्वों को एकजुट करने के लिए विदेश यात्रा करते हैं। भंडारी ने कहा कि राहुल गांधी की कांग्रेस अपने वैचारिक संरक्षक जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर भारतीय लोकतंत्र में अराजकता और अशांति फैलाना चाहती है।

विकास के नाम पर हो रहा विनाश, अरावली पहाड़ियों के विवाद के बीच आदित्य ठाकरे ने केंद्र सरकार पर बोला हमला

नई दिल्ली, (एजेंसी)। शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने मंगलवार को अरावली पहाड़ियों के विवाद को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए उस पर भारत के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा अरावली पहाड़ियों को नष्ट करने के प्रस्तावित कदम का बचाव करना शर्मनाक है। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्री का अरावली पहाड़ियों के प्रस्तावित विनाश का बचाव करना शर्मनाक है! पहली बात तो, पर्दाफाश होने के बाद झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? फिर, अगर अरावली पहाड़ियों का एक छोटा सा हिस्सा भी है, तो उसे खनन के लिए क्यों खोला जा रहा है? भाजपा भारत की पारिस्थितिकी को पूरी तरह नष्ट करने पर इतनी तुली क्यों है, ठीक वैसे ही जैसे वह हमारे सामाजिक ताने–बाने को नष्ट कर रही है? पोस्ट में लिखा कि आज अरावली पहाड़ियों की बात हो रही है, कल वे पश्चिमी घाट या हिमालय को खनन के लिए खोल देंगे! अरावली पहाड़ियों की रक्षा के लिए राजस्थान के सभी लोग जिस तरह सड़कों पर उतरे हैं, उसे देखकर वाकई प्रेरणा मिलती है। सरकार को अब हमारे प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए और अधिक प्रयास करने चाहिए – लेकिन यह उम्मीद मौजूदा सरकार से नहीं है! एक दिन पहले, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आश्वासन दिया था कि एनसीआर क्षेत्र में खनन की अनुमति नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले कुछ वर्षों में हरित अरावली से संबंधित मुद्दों में काफी वृद्धि हुई है। आंकड़ों के अनुसार, यादव ने कहा कि 2014 में जब देश में केवल 24 रामसर स्थल थे, तब से अब यह संख्या बढ़कर 96 हो गई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अरावली क्षेत्र के सुल्तानपुर, भिंडावास, असोला, सिलिसेरह और सांभर के रामसर स्थलों की घोषणा भाजपा सरकार के कार्यकाल में की गई थी।

संपादकीय

तमाम बातें हवाई ही बनी रहेंगी

पेरिस स्थित इनइक्वलिटी लैब की यह टिप्पणी महत्त्वपूर्ण है कि श्भारत दुनिया के उन देशों में है, जहां गैर–बराबरी उच्चतम स्तर पर है और जिसे कम करने की दिशा में हाल के वर्षों में कोई प्रगति नहीं हुई। वैसे तो यह पूरी दुनिया का हाल है कि आर्थिक गैर–बराबरी श्ऐतिहासिक रूप से उच्चतम स्तस्य पर पहुंच गई है और इसमें श्लगातार इजाफाय हो रहा है, लेकिन पेरिस स्थित इनइक्वालिटी लैब की ताजा रिपोर्ट का भारत के संदर्भ में एक अलग महत्त्व भी है। हाल में सरकारी एजेंसियों ने आंकड़ों के खेल से नैरेटिव बनाने की कोशिश की है कि नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियां आर्थिक विषमता को घटाने में कामयाब रही हैं। ऐसे में 200 विश्व–स्तरीय अर्थशास्त्रियों के श्रमसाध्य शोध से तैयार इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट में शामिल दो टिप्पणियां उल्लेखनीय हो जाती हैं। पहली यह कि श्भारत दुनिया के उन देशों में है, जहां गैर–बराबरी उच्चतम स्तर पर है और जिसे कम करने की दिशा में हाल के वर्षों में कोई प्रगति नहीं हुई हैयतथा यह कि श्भारत में आय, धन एवं लैंगिक लिहाज से हर स्तर पर विषमता मौजूद है, जो अर्थव्यवस्था के अंदर ढांचागत विभाजन पर रोशनी डालती है।य रिपोर्ट बताती है कि भारत में आमदनी संबंधी गैर–बराबरी की चौड़ी खाई मौजूद है, जबकि धन संबंधी विषमता की खाई उससे भी ज्यादा गहरी है। मसलन, नीचे की 50 फीसदी आबादी के पास कुल आमदनी का महज 15 फीसदी हिस्सा जाता है, जबकि शीर्ष एक प्रतिशत लोगों की जेब 22.6 प्रतिशत हिस्सा चला जाता है। धन की बात करें, तो निम्न आधी आबादी के पास देश के कुल धन का महज 6.4 प्रतिशत हिस्सा है, जबकि इसका 40.1 फीसदी हिस्सा टॉप एक प्रतिशत लोगों के पास है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि निम्न 50 प्रतिशत आबादी की औसत सालाना आय एक लाख रुपये से कम है, जबकि उसके बाद की 40 फीसदी आबादी की औसत सालाना आय साढ़े चार लाख रुपये से कम है। तो कुल मिलाकर जिसे भारत का बाजार का जाता है, वह टॉप दस प्रतिशत लोगों तक सीमित रह जाता है, जिनकी औसत सालाना आय पांच लाख से एक करोड़ रुपये तक है। स्पष्टतरू ये आंकड़े भारत के बारे में यथार्थवादी समझ बनाने का महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं। ऐसी समझ के बिना देश के विकास एवं प्रगति की तमाम बातें हवाई ही बनी रहेंगी।

अरावली को मृत्युदंड

पर्यावरण संरक्षण का मोदी सरकार का वादा उसके बाकी वादों की तरह न केवल खोखला है, बल्कि डरावना भी है। इस संरक्षण के नाम पर सरकार ने एक उद्योगपति को निजी जंगल बनाकर उसमें तमाम तरह के जानवर पालने की अनुमति दे दी। पूरी दुनिया में ऐसे भ्रष्टाचार की मिसाल नहीं मिलेगी। लेकिन पर्यावरण को लेकर सरकार के खौफनाक रवैये का यह अकेला उदाहरण नहीं है। नया उदाहरण 2 अरब साल पुरानी अरावली पर्वत श्रृंखला को सुप्रीम कोर्ट के जरिए मृत्युदंड सुनाने का है। सरकार की बनाई कमेटी की तय परिभाषा के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अरावली में खनन की जो अनुमति दी है, वह किसी मृत्युदंड से कम नहीं है।अगड़े–पिछड़े, लोकतांत्रिक–तानाशाही वाले तमाम देशों में पर्यावरण के मुद्दों पर व्यापक बहस होती है, फिर भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखकर फैसले लिए जाते हैं। लेकिन भारत शायद इकलौता देश है जहां सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर केंद्र की सिफारिश पर अपनी मुहर लगा दी और इसमें पर्यावरणविदों की राय जरूरी नहीं समझी गई। सरकार ने किसी पर्यावरणविद को भले सलाहकार नहीं बनाया, फिर भी अरावली में खनन के खिलाफ जो आवाजें चारों तरफ से उठ रही हैं, उन पर ही सर्वोच्च न्यायाल को स्वतरू संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर क्या गलत हो रहा है, जिस पर इतना विरोध हो रहा है।गौरतलब है कि अरावली पहाड़ियों की परिभाषा के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा पर्यावरण मंत्रालय, भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण, राज्यों के वन विभागों और सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी के सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई जिसे अरावली को परिभाषित करने को कहा गया। कमेटी ने कोर्ट के सामने अपनी अनुशंसा में कहा कि दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात इन चार राज्यों में लगभग 670 किमी तक फैली अरावली पहाड़ियों में वही पहाड़ियां अरावली श्रृंखला का हिस्सा मानी जायें जिनकी ऊंचाई 100 मीटर या उससे अधिक हो। भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार, पूरी अरावली श्रृंखला में 12,081 पहाड़ियां हैं जिनमें से मात्र 1048 पहाड़ियां ही यानी केवल 8.7 प्रतिशत हिस्सा ही सरकार के 100 मीटर के मानक पर खरी उतरता है। जिस पहाड़ी की ऊंचाई 99 मीटर है, उसे भी सरकार ने पहाड़ी नहीं माना है। कमेटी की अनुशंसाओं से असहमति जताते हुए न्यायमित्र वरिष्ठ वकील के. परमेश्वर ने अरावली श्रृंखला की नई परिभाषा का विरोध किया। उन्होंने कहा था कि भारतीय वन सर्वेक्षण ने इससे पहले अरावली की परिभाषा को लेकर जो नियम बनाये थे, उसके अनुसार, 3 डिग्री से अधिक ढाल, जिसमें घाटियों की चौड़ाई 500 मीटर हो, उसे अरावली श्रृंखला का हिस्सा समझा जाये, इसके अतिरिक्त पहाड़ी के नीचे (तलछटी) में 100 मीटर की चौड़ाई तक किसी भी किस्म की कोई गतिविधि ना की जाये। लेकिन अब तो नया खेल करके सौ मीटर ऊंचाई का मापदंड बना दिया गया है। जिसके बाद इन पहाड़ियों के मनचाहे खनन का खेल खेलने के लिए मैदान साफ है।कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 4 दिसंबर को द हिंदू में प्रकाशित अपने लेख में इसे श्अरावली के लिए एक डेथ वारंट यानी मृत्युदंड का ऐलान बताया था। उन्होंने लिखा था कि यह निर्णय उन समूहों के लिए वरदान है जो अवैध खनन और जमीन कब्जे में शामिल रहते हैं। सोनिया गांधी ने याद दिलाया कि अरावली सदियों से उत्तर भारत की जलवायु को संतुलित रखने, थार रेगिस्तान के फैलाव को रोकने और राजस्थान के जंगलों को संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि राजधानी दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण अब रोजमर्रा की समस्या नहीं रहा, बल्कि यह एक बड़े जन–स्वास्थ्य संकट का रूप ले चुका है। देश के दस बड़े शहरों में सालाना 30 हजार से अधिक मौतें सिर्फ प्रदूषण की वजह से हो रही हैं।दरअसल केंद्र सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम 1980 और वन संरक्षण नियम 2022 में संशोधन कर प्राकृतिक संसाधनों के गलत तरीके से दोहन का रास्ता खोला है, ताकि कुछ उद्योगपतियों के मुनाफे की हवस पूरी हो सके। इसके बदले भाजपा को करोड़ों का चंदा मिलता है, जिसका इस्तेमाल वो अपनी सत्ता बनाए रखने और मनमाने फैसले लेने में करती है। लेकिन माननीय अदालत को यह देखना चाहिए कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए न केवल करोड़ों लोगों को नुकसान में धकेला जा रहा है, बल्कि पर्यावरण को ऐसा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसकी भरपाई संभव नहीं होगी।अगर अदालत को कुछ वक्त बाद यह अहसास होगा कि अरावली पहाड़ों को खत्म करना ठीक नहीं था, तब भी इसका भूल सुधार नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो पहाड़ दो अरब सालों में बने हैं, मजबूत हुए हैं, उन्हें फिर हासिल नहीं किया जा सकेगा। ध्यान रहे कि अरावली पर्वतमाला करोड़ों सालों से थार मरुस्थल को पूर्व की ओर बढ़ने से रोक रही है। सिंधु–गंगा के उर्वर मैदान को रेगिस्तान बनने से रोक रही है। चंबल, साबरमती और लूनी जैसी नदियों को इन पहाड़ों से जीवन मिला है। करोड़ों साल पुराने एक सम्पूर्ण पारिस्थितिकीय तंत्र को एक श्तथाकथित विशेषज्ञ कमेटीश ने सिर्फ एक श्ऊंचाईश से परिभाषित कर दिया है, यह बड़ी विडंबना है। अरावली मौसम को संतुलित करने की पुरानी ढाल है, जिसमें अब जगह–जगह सुराख किए जा चुके हैं। 92 प्रतिशत अरावली को नकारकर हम आने वाली पीढ़ियों के साथ गुनाह करेंगे। मोदी सरकार तो लोककल्याण का मतलब ही भूल चुकी है, उसे न खामोश खड़े जंगल, पहाड़ दिखाई देते हैं, न ही प्रदूषण की त्रासदी से तड़पते लोग दिखते हैं।

राम के नाम पर रोजगार गारंटी का राम नाम सत्य

गौरव

मनरेगा में काम की मांग जमीन से आती थी, लेकिन वी बी जी राम जी के इस नए कानून में केन्द्र सरकार तय करेगी कि किस राज्य को कितना आबंटन होना है। अब एक प्रश्न यह है कि दिल्ली में बैठा बाबू कैसे तय करेगा कि राजस्थान में कितने वॉटर शेड बनने हैं या मध्यप्रदेश में कितने तालाब! यानी मूल तौर पर ये नया कानून कहता है कि अब बजट केन्द्र सरकार आधा ही देगी लेकिन फैसले सारे दिल्ली में होंगे। भारत सरकार द्वारा संसद में मनरेगा को हटाकर, वी बी–जी राम जी नाम से नया रोजगार कानून लाया गया है। जल्दबाजी में किये गये इस बदलाव पर संसद में विपक्ष द्वारा की गई बहस भी मनरेगा जैसे व्यापक कार्यक्रम के संदर्भ से बहुत ही कमजोर रही। जिससे ये जाहिर होता है कि आज सत्ता के साथ विपक्ष में बैठे जनप्रतिनिधि भी जमीनी हकीकध्त से कितने दूर हैं। जो बहस ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था, सामाजिकता और राजनीति पर हो सकती थी वह महात्मा गांधी के नाम को हटाने पर सीमित होकर रह गई। आने वाले समय में इसका खामियाजा देश के मजदूरों को उठाना होगा।दो दशकों के बाद हुए इस बदलाव के मद्देनजर जरूरी है कि एक बार मनरेगा के पूरे सफर को समझने की कोशिश की जाये और ये भी समझने की कोशिश की जाये कि नये कानून से क्या बदलेगा और कैसे बदलेगा। दरअसल, 2005 में मनरेगा एक कानून की तरह लाया गया। देखने में यह एक सरकारी योजना जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे की बड़ी सोच यह थी कि योजना के छोटे दायरे में रखने के बजाय इसे कानून बनाया जाये और इस तरह देश के हर ग्रामीण नागरिक को रोजगार का कानूनन अधिकार इस बिल ने दिया। सरकारी योजना एक तरह से सरकारी कृपा की तरह लोगों तक पहुंचती है लेकिन मनरेगा अधिकार के रूप में लोगों तक पहुंचा। इसीलिए इसे रोजगार सृजन कार्यक्रम की तरह न देखते हुए देश के हर ग्रामीण नागरिक के सशक्तिकरण के कदम की तरह देखा जाना चाहिये। यही कारण है कि इसे हटाने के लिए भी सरकार को आज संसद में इतना जोर लगाना पड़ रहा है।इससे पहले की ये समझा जाये के मनरेगा से क्या हुआ, पहले इस अंतर को समझते हैं कि मनरेगा कैसे संसद में पास हुआ था और श्वी बी जी राम जीश कैसे पास हुआ है! मनरेगा कानून का प्रारूप बनने से पहले 2003–04 में देश के कई ग्रामीण इलाकों में मजदूर संगठनों द्वारा ऐसे एक कानून की मांग की मुहिम शुरू हुई, हालांकि ये मांग नई नहीं थी लेकिन पहली बार एक निर्णायक मांग की तरह जगह–जगह सामाजिक कार्यर्ताओं और मजदूर संगठनों ने ऐसे कानून की तैयारी शुरू की। जिसके नतीजतन जनांदोलनों द्वारा बनाए गए पहले प्रारूप को 2004 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में प्रस्तुत किया गया, जहां इस पर पहली चर्चा हुई। फिर वहां से बिल प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचा, वहां से ग्रामीण विकास मंत्रालय और फिर लोकसभा में पेश हुआ। लोकसभा में आने के बाद मनरेगा का ये विधेयक संसद की स्थायी समिति में गया जहां फिर इसमें कई संशोधन किये गये।यहां गौरतलब बात ये है कि तब इस समिति के मुखिया भाजपा सांसद कल्याण सिंह हुआ करते थे। समिति से आने के बाद सारे संशोधनों को शामिल करते हुए 2005 में जब ये कानून संसद से पास हुआ तो पूर्ण सर्वसम्मति से सभी दलों ने इसका समर्थन किया था। वहीं श्वी बी जी राम जीश के मामले में दिल्ली में बैठे अफसरों द्वारा तैयार प्रारूप को संसद के पटल पर रख दिया गया। जनता से राय–सुझाव मांगना तो दूर की बात है, यह प्रारूप स्थायी समिति को भी न भेजकर, विपक्ष के विरोध और नारेबाजी के बीच ध्वनि मत से पारित करवा दिया गया। जिन राज्य सरकारों से इसके अनुपालन में बजट की हिस्सेदारी अपेक्षित है उन तक से कोई संवाद नहीं किया गया। यानी एक तरफ मनरेगा जमीनी आवाज के तौर पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से होकर संसद पहुंचा था वहीं श्वी बी जी राम जीश मुठ्ठी भर अफसरों का कारनामा है जिसे प्रधानमंत्री कार्यालय से होकर देश में लागू कर दिया गया है।अब देखते हैं कि पिछले बीस सालों में मनरेगा से क्या देश को कोई फायदा हुआ? 2005 में जब मनरेगा लागू हुआ, ये इतना व्यापक कानून था कि पूरे देश मे लागू होने में ही इसे लगभग तीन साल लगे। पहले वर्ष में जब ये नरेगा हुआ करता था

तब बजट में 11.3 हजार करोड़ का पहला आबंटन हुआ। वहीं पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा में 86 हजार करोड़ का आबंटन हुआ। इन पिछले बीस वर्षों में कुल लगभग साढ़े 10 लाख करोड़ रुपये अलग–अलग सरकारों द्वारा मनरेगा को आवंटित किये गये। इस साढ़े 10 लाख करोड़ से क्या हुआ– इसे यदि सतही तौर पर समझा जाये तो ग्रामीण क्षेत्रों में कई तालाब, ट्रेंच, वॉटर शेड, सड़क, शौचालय जैसे निर्माण कार्य हुए और इस प्रक्रिया में मजदूरों को काम मिला। काम मिलने से संभवतरू पलायन भी कम हुआ होगा। लेकिन मनरेगा जैसे व्यापक विचार को सिर्फ रोजगार सृजन के कार्यक्रम की तरह देखना ही सबसे बड़ी चूक होगी। इसे एक आर्थिक नीति की तरह देखा जाना चाहिये जिसने जमीन पर कुछ सामाजिक और राजनैतिक प्रभाव भी पैदा किये।पहला तो यह कि जो विशाल धनराशि मनरेगा में खर्च हुई, वह केंद्र सरकार की तिजोरी से सीधे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पहुंची, जिससे पिछले बीस वर्षों में भारत के गांवों में विकसित हो रहे बाजार को बड़ी बहुत बड़ी मदद मिली। मजदूर के पास आए पैसे की विशेषता यह होती है कि वह रुकता नहीं है, सीधे बाजार में आता है और इसीलिए मनरेगा में खर्च हुए इस पैसे ने गांव–गांव में कपड़े, राशन किराना, हार्डवेयर, मोबाइल फोन जैसे व्यापार को बढ़ाया। आज गांवों कस्बों में जो हम ये दुकानें देखते हैं, उसमें मनरेगा के इस साढ़े 10 लाख करोड़ की बड़ी भूमिका है। दूसरा बड़ा काम यह हुआ कि जैसे–जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पैसा बढ़ा, देश के गांव भी बड़े बाजार का हिस्सा होते गए। एक उदाहरण के तौर पर महिन्द्रा, फोर्स मोटर्स, बजाज मोटर्स, हीरो जैसी बड़ी कंपनियां– जो बोलेरो, मार्शल, ट्रैक्स, तूफान जैसे एसयूवी के मॉडल ग्रामीण भारत को ध्यान में रखकर बाजार में लाई, उनमें बम्पर सेल मिली। वहीं बजाज, हीरो और टीवीएस जैसी कंपनियों ने कम कीमत की मोटर साइकिलों की जोरदार बिक्री गांवों में की। आज यही कंपनियां भारत में बनी अपनी गाड़ियां विदेशों को निर्यात करने लगी हैं जिससे देश की जीडीपी बढ़ती है और सरकार बढ़ती अर्थव्यवस्था के आंकड़े दिखा पाती है। इस वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा मनरेगा का यही बजट था। तीसरा एक बड़ा काम यह हुआ कि ग्राम पंचायत एक संस्था के रूप में और सशक्त हुई। ग्राम पंचायतों को रोजगार सहायक के रूप में एक सहयोगी मिला। आम नागरिकों और ग्राम पंचायतों के बीच संपर्क, संवाद और निर्भरता बढ़ी, जो ग्राम स्वराज की दिशा में बड़ा कदम रहा। चौथा, लगभग सभी बड़े राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण है, वहीं अनुसूचित क्षेत्रों में आरक्षण भी है जो इस व्यवस्था में हाशिये के समुदायों को प्रतिनिधित्व का मौका देता है। मनरेगा ने त्रिस्तरीय व्यवस्था में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और अनुसूचित जाति–जनजाति से आने वाले लोग हैं उन्हें पद के साथ आर्थिक निर्णय लेने की ताकध्त दी। जिससे इन समुदायों से सक्षम नेतृत्व निकलने के रास्ते खुले। पांचवा, मनरेगा की व्यवस्था में पारदर्शिता के लिए दो बड़ी बातें थीं एक था– सोशल ऑडिट, जो ग्रामीण नागरिकों को मनरेगा के अंतर्गत हुए।

देश में ध्रुवीकरण की कोशिशें तेज

नीरज

बिहार चुनाव जीतने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प.बंगाल और असम जैसे चुनावी राज्यों में सक्रिय हो गए हैं। बीते दो दिनों में उनकी दो सभाएं प.बंगाल और असम में हुईं। प.बंगाल के नादिया जिले में उनका हेलीकॉप्टर धुंध की वजह से न उतर सका तो उन्होंने कोलकाता से ही वर्चुअली सभा को संबोधित किया, जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाल बाहर करने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि नादिया में उनके खिलाफ पोस्टर और बैनर लगे थे, जिसके बाद सवाल उठता है कि क्या श्री मोदी विरोध का सामना करने से डर गए और इसलिए धुंध को लौटने का कारण बताया जा रहा है। क्योंकि पंजाब चुनाव के वक्त वे किसानों के विरोध की वजह से बीच रास्ते से लौट आए थे और तब उन्होंने कहा था कि अपने मुख्यमंत्री से कहना मैं जिंदा वापस लौट आया। लोकतांत्रिक देश में जनता के विरोध को जान पर खतरे की तरह दिखाना यह बताता है कि प्रधानमंत्री को लोकतंत्र में जनता को मिले अधिकार सुहाते नहीं हैं। खैर, ठंड का मौसम बीतेगा और धुंध खत्म होगी, तब तो नरेन्द्र मोदी को बंगाल में प्रचार के लिए जाना ही होगा, तब अगर विरोध होता है, तो कितनी बार वे लौटेंगे, ये देखना होगा। प.बंगाल में नरेन्द्र मोदी असम गए और वहां उन्होंने इतिहास की गलत बयानी कर पं. नेहरू और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। लेकिन इस कोशिश में श्री मोदी ने खुद को उपहास का पात्र बना दिया है कि आखिर कब तक वे इतिहास को तोड़–मरोड़ कर पेश करेंगे। दरअसल श्री मोदी ने 20 दिसंबर को गुवाहाटी में आरोप लगाया कि श्कांग्रेस ने स्वतंत्रता से पहले ही इस जगह की पहचान मिटाने की साजिश रची थी, जब मुस्लिम लीग और ब्रिटिश ताकतें मिलकर भारत को बांटने की जमीन तैयार कर रही थीं, उस समय असम को भी पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की योजना थी। कांग्रेस भी उस साजिश का हिस्सा बनने वाली थी। तब बोरदोलोई जी ने अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े होकर असम की पहचान मिटाने की इस कोशिश का विरोध किया और असम को देश से अलग होने से बचाया।श्लेकिन हकीकत यह है कि मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राजनीतिक नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए तीन ब्रिटिश कैबिनेट सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था, जिसमें ब्रिटिश भारत के लिए तीन स्तरीय प्रशासनिक संरचना का प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें शीर्ष स्तर पर संघीय संघ, निचले स्तर पर अलग–अलग प्रांत और मध्य स्तर पर प्रांतों के समूह थे। उत्तर–पश्चिम भारत, पूर्वी भारत और भारत के शेष मध्य भागों के लिए समूह ए, बी और सी नामक तीन समूहों का प्रस्ताव रखा गया था। समूह ए में हिंदू बहुल प्रांत (जैसे बॉम्बे, मद्रास, यूपी) थे, समूह बी में मुस्लिम बहुल प्रांत (पंजाब, सिंध, उत्तर–पश्चिमी सीमांत प्रांत) थे और समूह सी में बंगाल और असम, जिसमें बंगाल मुस्लिम बहुल था, जबकि असम हिंदू बहुल। मुस्लिम लीग चाहती थी कि पूरा समूह सी पाकिस्तान का हिस्सा बने। लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं थी। न ही कांग्रेस ये चाहती थी कि असम को बंगाल के साथ मिलाया जाए। 29 दिसंबर 1946 के श्हरिजनश अखबार में श्गांधीजी की असम को सलाहश शीर्षक से प्रकाशित लेख में इसका स्पष्ट उल्लेख है। नेहरू भी असम को पाकिस्तान या बंगाल के साथ मिलाने के खिलाफ थे। 22 जुलाई 1946 को गोपीनाथ बोरदोलोई को पत्र में नेहरूजी ने लिखा, श्समूह के खिलाफ फैसला करना सही और उचित था।श इसके बाद 23 सितंबर 1946 को लिखा, श्किसी भी हालत में हम असम जैसे प्रांत को उसकी इच्छा के खिलाफ कुछ करने के लिए मजबूर करने पर सहमत नहीं होंगे।श अप्रैल 1946 में बीबीसी को दिए इंटरव्यू में पं. नेहरू ने कहा, श्उत्तर–पश्चिम सीमा प्रांत में मुस्लिम बहुल होने के बावजूद लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया... असम भी स्पष्ट रूप से पाकिस्तान के खिलाफ है।श कांग्रेस के जबरदस्त विरोध के बाद अंग्रेजों ने असम को पाकिस्तान में मिलाने की योजना को रद्द कर दिया। कैबिनेट मिशन प्लान को कांग्रेस ने पूरी तरह नाकाम कर दिया। नेहरू के 10 जुलाई 1946 के प्रेस कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस की स्पष्ट अस्वीकृति और असहमति माना गया। ये सारी बातें सौ साल पुरानी भी नहीं हैं, तब के अखबारों की कतरनों में देखा जा सकता है कि गांधी, नेहरू, कांग्रेस पार्टी और गोपीनाथ बोरदोलोई सबके विचार इस मुद्दे पर एक जैसे थे। लेकिन नरेन्द्र मोदी कह रहे हैं कि बोरदोलोई ने अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े होकर असम बचाया।दरअसल असम में अब भाजपा के खिलाफ एंटीइनकमबेंसी दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस गौरव गोगोई के नेतृत्व में वहां लगातार जमीन पर सक्रिय है। इसलिए भाजपा अब वहां झूठा इतिहास बताकर कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश में है, जिसमें नरेन्द्र मोदी का पहला ही दांव बेकार गया है। असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा भी भाजपा शुरु से उठाती रही है और हिमंता बिस्वासरमा लगातार सांप्रदायिक विभेद बढ़ाने वाले फैसले

ले रहे हैं, इनका लाभ भाजपा को मिलेगा या नहीं देखना होगा।पं.बंगाल में भी नरेन्द्र मोदी यही कोशिश कर रहे हैं। हुमायूं कबीर जैसे नेता बाबरी मस्जिद बनवाने की शुरुआत कर परोक्ष रूप से ध्रुवीकरण में भाजपा की मदद कर रहे हैं। बचा हुआ काम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत पूरा करने की कोशिश में है। श्री भागवत ने रविवार को कोलकाता में कहा कि यदि सभी हिंदू एकजुट होकर खड़े हो जाएं, तो प. बंगाल की स्थिति को बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उनका यह बयान चुनावी पृष्ठभूमि तैयार करने की तरह देखा जा रहा है। भले संघ खुद को एनजीओ बताए, लेकिन वह खुलकर राजनीति कर रहा है। मोहन भागवत अपने बयान में संविधान की अवहेलना करते भी दिखे, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। अगर संसद कभी संविधान में संशोधन करके वह शब्द जोड़ने का फैसला करती है, तो करें या न करें, ठीक है। हमें उस शब्द की परवाह नहीं है क्योंकि हम हिंदू हैं, और हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है। यही सत्य है।संघ प्रमुख ने मोदी सरकार को इशारा दे दिया है कि अब संविधान में संशोधन कर हिंदू राष्ट्र का ऐलान उसका अगला पड़ाव होगा। मोहन भागवत और नरेन्द्र मोदी दोनों के बयान खतरनाक हैं और देश में ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने वाले हैं। इससे भले उन्हें सत्ता मिल जाए, लेकिन इसका जो दीर्घकालिक नुकसान देश को होगा, वह चिंतनीय है।

सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण देश में असमानता

अजीत द्विवेदी

यह निष्कर्ष पुराना है कि भारत एक गहरी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक असमानता वाला देश है। सामाजिक असमानता में जातीय, धार्मिक और लैंगिक असमानता सब शामिल है। यह निष्कर्ष हर साल आने वाली इनइक्वलिटी लैब की रिपोर्ट से प्रमाणित होता है। इस साल की फ्रांस की इनइक्वलिटी लैब की रिपोर्ट बुधवार, 10 दिसंबर को प्रकाशित हुई। पिछले साल के मुकाबले इस रिपोर्ट में ज्यादा कुछ नहीं बदला है। भारत की एक फीसदी आबादी के पास देश की 40 फीसदी संपत्ति है। अगर इसका दायरा थोड़ा बड़ा करें तो दिखेगा कि शीर्ष 10 फीसदी आबादी के पास कुल संपत्ति का 65 फीसदी हिस्सा है। इनकी तुलना में सबसे नीचे के 50 फीसदी लोगों को देखें तो उनके पास सिर्फ 6.4 फीसदी दौलत है। इसका मतलब है कि बीच के 40 फीसदी यानी मध्य वर्ग के पास 30 फीसदी से कुछ कम संपत्ति है। दुनिया के स्तर पर यह असमानता थोड़ी ज्यादा दिखती है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सिर्फ 60 हजार लोगों यानी कुल आबादी के 0.001 फीसदी के पास इतनी संपत्ति है, जितनी नीचे की 50 फीसदी आबादी के पास नहीं है। दुनिया की आधी आबादी यानी करीब चार सौ करोड़ लोगों से ज्यादा संपत्ति सिर्फ 60 हजार लोगों के पास है। असमानता की ताजा रिपोर्ट से यह मिथक भी टूटा है कि मौजूदा सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण देश में असमानता बढ़ रही है। असल में भारत में पहले जो आर्थिक असमानता थी इस सरकार ने उसी को मेंटेन किया है। देश के सबसे अमीर 10 फीसदी लोगों और सबसे गरीब 50 फीसदी लोगों की आय के बीच 2014 में 38 फीसदी का अंतर था, जो 2024 में 38.2 फीसदी हुआ है। यानी दोनों की आय की असमानता लगभग उतनी ही है, जितनी 10 साल पहले थी। इसका अर्थ है कि भारत की आर्थिक नीतियों की निरंतरता कायम है। जिन नीतियों ने असमानता को बढ़ाया उन्हें जारी रखा गया है। अगर स्थायी संपत्ति की बात छोड़ें तो देश में हर साल जो आय उत्पादित हो रही है उसका 58 फीसदी हिस्सा ऊपर की 10 फीसदी आबादी के पास जा रहा है और नीचे की 50 फीसदी आबादी के पास आय का सिर्फ 15 फीसदी हिस्सा जा रहा है। यानी जिन लोगों के पास 65 फीसदी संपत्ति है उनके पास कुल आय का 58 फीसदी जा रहा है और जिनकी कुल संपत्ति 6.4 फीसदी है उनके पास कुल आय का 15 फीसदी जा रहा है। अगर रुपए के हिसाब से देखें तो भारत में नीचे की 50 फीसदी आबादी की प्रति व्यक्ति सालाना आय एक लाख रुपए से कम है। यानी 70 करोड़ की आबादी की प्रति व्यक्ति मासिक आय आठ हजार रुपए के करीब है। इनके मुकाबले एक फीसदी आबादी यानी एक करोड़ 40 लाख टॉप लोगों की औसत सालाना आय डेढ़ करोड़ रुपए के करीब है। इस वर्ग के लोग औसतन हर महीना 12 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं। सोचें, आठ हजार रुपए और 12 लाख रुपए महीना के फर्क पर! अगर टॉप 10 फीसदी की आय देखें तो उनकी औसत सालाना आय 40 लाख रुपए के करीब है। उसके बाद मध्य वर्ग के 40 फीसदी लोग आते हैं, जिनकी औसत सालाना आय साढ़े चार लाख रुपए के करीब है यानी 40 हजार रुपया महीना से कम। इस असमानता को अगर जाति, धर्म, लिंग और क्षेत्र के हिसाब से देखेंगे तो और भयावह तस्वीर सामने आएगी। देश के सबसे पिछड़े राज्य बिहार में तो एक करोड़ परिवार ऐसे हैं, जिनकी मासिक आमदनी छह हजार रुपए है। यह बिहार सरकार की ओर से कराई गई जाति गणना में पता चला। इसका मतलब है कि करीब पांच करोड़ लोग ऐसे हैं, जो महीने का 12 सौ रुपया कमाते हैं। भारत में अपनाई गई आर्थिक नीतियों को देखते हुए कह सकते हैं कि निकट भविष्य में इस स्थिति में सुधार की कोई संभावना नहीं दिख रही है। भारत लंबे समय से ट्रिकल डाउन थ्योरी पर चल रहा है। इसका अर्थ है कि ऊपर वालों का घड़ा भर जाएगा तो उसमें रिस कर नीचे गिरना शुरू होगा, जिससे बाकी लोगों का भला होगा। लेकिन मुश्किल यह है कि ऊपर वाले लगातार अपने घड़े का आकार बढ़ाते जा रहे हैं। उनका घड़ा भरने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तभी भारत की बड़ी आबादी सरकार प्रायोजित सर्वाइवल स्कीम्स पर पल रही है। इस रिपोर्ट में एक खास बात यह है कि आजादी के बाद एक समय ऐसा आया था, जब टॉप 10 फीसदी और बॉटम 50 फीसदी के बीच का अंतर काफी कम हो गया था। वह अच्छा था या बुरा यह अलग विश्लेषण का विषय है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आजादी के बाद जो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाली नीति अपनाई गई थी उसने निजी तौर पर लोगों के बेहिसाब दौलत इकत्र्ठा करने या बेहिसाब कमाई करने पर रोक लगाई थी। ब्रिटिश शासन में ऊपर के 10 फीसदी और नीचे के 50 फीसदी के बीच जो अंतर था वह 1940 से कम होना शुरू हुआ था और 1980 के दशक में सबसे कम था। 1983–84 के आसपास भारत के शीर्ष 10 फीसदी लोगों की कुल आय में हिस्सेदारी 30 फीसदी से नीचे आ गई थी, जबकि नीचे के 50 फीसदी की हिस्सेदारी बढ़ कर 23 फीसदी तक पहुंच गई थी। परंतु 1991 में अपनाई गई उदार आर्थिक नीतियों के बाद एक बार फिर असमानता बढ़ने लगी। 2024 में नीचे के 50 फीसदी की आय 15 फीसदी पर आ गई और ऊपर के 10 फीसदी की आय 58 फीसदी पहुंच गई। इसमें टॉप एक फीसदी के पास कुल आय का 22.6 फीसदी जा रहा है। जब मिश्रित अर्थव्यवस्था थी तब सरकार माईबाप थी लेकिन उस समय कम आबादी सरकार माईबाप पर निर्भर थी। आज ज्यादा बड़ी आबादी माईबाप सरकार की ओर से प्रायोजित सर्वाइवल स्कीम्स पर निर्भर है। अब सवाल है कि भारत में अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों से भी ज्यादा असमानता होने का मूल कारण क्या है? इसके कई कारण हैं और गौर से देखें तो सारे कारण सामने दिखते हैं। सरकार श्सबका साथ, सबका विकासय की बात करती है लेकिन असल में सबके साथ से कुछ लोगों का विकास होता है। भारत में टैक्स का सिस्टम ऐसा है कि देश के गरीब से गरीब आदमी को भी वैसे ही अप्रत्यक्ष कर यानी जीएसटी भरना है, जैसे अमीर आदमी को भरना है। दूसरी ओर अमीर आदमी के लिए कॉरपोरेट टैक्स में भारी भरकम छूट से लेकर बैंकों का कर्ज माफ होने तक की सुविधा है। मजदूरों और पेशेवरों की मजदूरी या वेतन कछुआ चाल से बढ़ रहा है, जबकि कॉरपोरेट मुनाफा, शेयर बाजार की कमाई और रियल इस्टेट की आय दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट नहीं बढ़ा रही है। इसका नतीजा है कि गरीब और मध्य वर्ग की ठहरी हुई कमाई का बड़ा हिस्सा शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च होता है। ऐसे में उसकी संपत्ति कहां से बढ़ेगी? सरकार डंका पीटती है कि रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हो रहा है लेकिन उस टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है यह कभी नहीं बताया जाता है।

पुलिस बल का मनोबल, संवेदनशील व्यवहार एवं आपसी समन्वय सर्वोपरि - पुलिस आयुक्त प्रयागराज

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।माघ मेला की तैयारियों को लेकर रिजर्व पुलिस लाइन्स,माघ मेला स्थित तीर्थराज सभागार में पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संयुक्त बैठक हुई।बैठक मे अपर पुलिस आयुक्त प्रयागराज डॉ. अजय पाल शर्मा द्वारा संबोधित किया गया।उन्होंने माघ मेला को एक अत्यंत संवेदनशील आयोजन बताते हुए विभिन्न चरणों में आयोजित किए जा रहे प्रशिक्षणों को गंभीरता से लेने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि मेले में हर वर्ग के श्रद्धालुओं का आगमन होता है, ऐसे में समय रहते भीड़ का सही आकलन कर उचित निर्णय लेना आवश्यक है। उन्होंने बल को शारीरिक एवं मानसिक रूप से तैयार रहने की अपील की।इसके उपरान्त मेलाधिकारी श्री ऋषि राज ने बल को संबोधित करते हुए मेला क्षेत्र एवं सेक्टरों को स्वयं भ्रमण कर भली–भांति समझने पर जोर दिया। पॉन्टून पुलों की भूमिका तथा विशिष्टध्अतिविशिष्ट महानुभावों के आगमन के दौरान संयमित व्यवहार की आवश्यकता पर भी उन्होंने बल दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस ड्यूटी में स्वभाव एवं व्यवहार सबसे महत्वपूर्ण है तथा सड़क किनारे किसी को सोने नहीं दिया जाना चाहिए।इसके पश्चात नगर आयुक्त श्री साईं तेजा द्वारा मेला ड्यूटी को प्रशासनिक समन्वय का उदाहरण बताते हुए सभी विभागों के साथ तालमेल बनाकर कार्य करने की अपील की गई। जिलाधिकारी प्रयागराज श्री मनीष कुमार वर्मा ने माघ मेला को हर वर्ष एक नई चुनौती बताते हुए कहा कि गंगा नदी की ध ाारा में परिवर्तन के कारण घाटों की स्थिति बदल सकती है, इसलिए पूर्व में ड्यूटी कर चुके कर्मी भी मेला क्षेत्र का पुनः भ्रमण करें। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के कार्मिक ड्यूटी में रहते हैं, परंतु वर्दी में होने के कारण जनता की अपेक्षाएँ पुलिस से अधिक होती हैं। इस विश्वास को बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने मुख्य स्नान पर्वों पर मोबाइल संचार बाधित होने की संभावना को देखते हुए एक से अधिक संपर्क साधन रखने तथा टीम भावना से कार्य करने की अपील की।अंत में पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट प्रयागराज जोगिंदर कुमार ने पुलिस बल को संबोधित करते हुए कहा कि माघ मेला एक महत्वपूर्ण ध ार्मिक आयोजन है, जिस पर शासन एवं देशभर की निगाह रहती है। उन्होंने पुलिस बल का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि यह ड्यूटी नहीं, बल्कि सेवा का अवसर है। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपेक्षा की कि वे पूर्ण निष्ठा, अनुशासन एवं संवेदनशीलता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें तथा श्रद्धालुओं एवं साधु–संतों के साथ शालीन एवं सहयोगात्मक व्यवहार सुनिश्चित करें।पुलिस आयुक्त ने निर्देशित किया कि सभी पुलिसकर्मी मेला क्षेत्र की भौगोलिक संरचना, प्रमुख मार्गों, घाटों एवं संवेदनशील स्थलों की जानकारी स्वयं प्राप्त करें।साथ ही सभी राजपत्रित अधिकारी एवं थाना प्रभारी अपने अधीनस्थों से भली–भांति परिचित रहें, उनकी समस्याओं का समाधान करें, पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाएँ तथा सभी संबंधित विभागों एवं आपात सेवाओं के मोबाइल नंबर अपने पास रखें, जिससे प्रभावी आपसी समन्वय सुनिश्चित हो सके।

इस कार्यक्रम में अपर पुलिस आयुक्त प्रयागराज डॉ. अजय पाल शर्मा, जिलाधिकारी प्रयागराज मनीष कुमार वर्मा, मेलाधिकारी ऋषि राज, अपर जिलाधिकारी (नगर), नगर आयुक्त साईं तेजा, पुलिस अधीक्षक माघ मेला श्री नीरज कुमार पाण्डेय, सहायक पुलिस आयुक्त राजकुमार मीणा, सहायक नोडल पुलिस अधिकारी माघ मेला विजय आनन्द सहित माघ मेला से जुड़े अन्य राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारी, पीएसी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एवं अन्य संबंधित विभागों के कार्मिक उपस्थित रहे।

एक के बाद एक भिड़ंत चार ट्रक–जनरथ बस और कार

लखनऊ, (संवाददाता)। यूपी के अमेठी में मंगलवार सुबह लखनऊ–वाराणसी हाईवे पर भीषण हादसा हो गया। यहां एक के बाद एक चार ट्रक, जनरथ बस और कार आपस में भिड़ गए। हादसे में दो ट्रक चालकों की मौत हुई है। जबकि, 16 यात्री घायल हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसा मुसाफिरखाना क्षेत्र में मंगलम स्कूल के पास हुआ। सीओ अतुल सिंह ने बताया कि कोहरे के कारण एक ट्रक डिवाइडर पर चढ़ गया। इसके ठीक पीछे आ रहा ट्रक इससे भिड़ गया। इसी बीच एक और ट्रक पीछे वाले ट्रक से टकरा गया। इसके बाद एक और ट्रक, जनरथ बस व कार क्षतिग्रस्त ट्रकों से टकरा गए। हादसे में दो ट्रक चालकों की मौत हो गई। वहीं जनरथ बस में बैठे 16 यात्री घायल हो गए।

संक्षिप्त खबरें

बॉक्सिंग में रिंकी, काजल और रश्मि ने बनाई अगले दौर में जगह

लखनऊ, (संवाददाता)। झांसी की रिंकी किशोरी, वाराणसी की काजल और आगरा की रश्मि बघेल ने अपने मुकाबले जीतते हुए राज्य महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लाइट फ्लाईवेट (45–48 किग्रा भारवर्ग) के दूसरे दौर में प्रवेश किया। रिंकी ने में प्रयागराज की हर्षिता मिश्रा, काजल कानपुर की शिवांगी पाल और रश्मि ने गोरखपुर की तनु को हराया। केडी सिंह बाबू स्टेडियम के बॉक्सिंग एरीना में आयोजित प्रतियोगिता में सोमवार को प्रारंभिक दौर के मुकाबले खेले गए। प्रतियोगिता के फ्लाईवेट (48–51 किग्रा भारवर्ग) में अलीगढ़ की कुसुम ने झांसी की अनीशा यादव, सहारनपुर की अंशिका त्यागी ने आगरा की मानसी, मुरादाबाद की सेजल शर्मा ने वाराणसी की प्रीति पटेल और मेरठ की राशि शर्मा ने कानपुर की शीलू को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। प्रतियोगिता के बेंटम वेट (51–54 किग्रा भारवर्ग) में पहले दौर के मुकाबलों में प्रयागराज की सानिया नफीस ने बरेली की साक्षी मथुरिया, आगरा की बबिता ने गोरखपुर की अर्पिता कुशवाहा, झांसी की निदा खान ने अलीगढ़ की रायबिन को पराजित किया। इसके अलावा वेल्टरवेट (54–57 किग्रा भारवर्ग) के एकमात्र मुकाबले में आगरा की अंजली चाहर ने शशि यादव को हराते हुए दूसरे दौर में जगह बनाई।

एआई आधारित स्मार्ट खेती है भविष्य की जरूरत

लखनऊ, (संवाददाता)। इंटीग्रल विश्वविद्यालय के इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सोमवार को दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कृषि कांग्रेस– विबकॉन–2025 की शुरूआत हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उप्र सरकार के राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि एआई आधारित स्मार्ट खेती भविष्य की जरूरत है। आधुनिक तकनीक अपनाने से खेती की लागत घटेगी, उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। विकसित भारत के लिए एआई व रोबोटिक्स आधारित स्मार्ट कृषि विषय पर आधारित इस इस सम्मेलन में खेती में एआई, रोबोटिक्स, ड्रोन, स्मार्ट मशीनों और नई तकनीकों के उपयोग पर सरल और उपयोगी चर्चा की गई। इंटीग्रल विश्वविद्यालय के संस्थापक व कुलपति प्रो. एस. डब्ल्यू. अख्तर ने कहा कि तकनीक आधारित खेती से ग्रामीण विकास को नई दिशा मिलेगी। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के कुलपति प्रो. पंजाब सिंह ने जलवायु परिवर्तन, जल संकट और घटती भूमि गुणवत्ता को बड़ी चुनौती बताते हुए स्मार्ट खेती को इसका समाधान बताया। उप्र. कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से आयोजित इस सम्मेलन में देश–विदेश से आए कृषि वैज्ञानिक, शिक्षाविद, नीति–निर्माता, उद्योग विशेषज्ञ, कृषि उद्यमी और प्रगतिशील किसान शामिल हुए। अफ्रीकन–एशियन रूरल डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन के महासचिव डॉ. मनोज एन. सिंह ने वैश्विक स्तर पर एआई की भूमिका पर बात की। भारत में गांबिया के उच्चायुक्त मुस्तफा जवारा ने देशों के बीच सहयोग और अनुभव साझा करने पर जोर दिया। सम्मेलन में विबकॉन–2025 एक्सपो में एआई आधारित कृषि उपकरण, रोबोटिक्स मशीनें और नई तकनीकों के मॉडल प्रदर्शित किए गए , जो किसानों और विद्यार्थियों के लिए खास आकर्षण रहे। कार्यक्रम का संयोजन प्रो. मो. हारिस सिद्दीकी और संचालन प्रो. अलवीना फारूकी व प्रो. सबा सिद्दीकी ने किया।

रोडवेज पर लगा स्वास्थ्य शिविर

अयोध्या। कोहरे को देखते हुए बुधवार को अयोध्या बस स्टेशन परिसर पर सामान्य स्वास्थ्य जांच एवं उपचार के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया।इस मौके पर क्षेत्रीय प्रबंधक विमल राजन,सहायक प्रबंधक रोडवेज आदित्य प्रकाश मौजूद रहे।इस मौके डीटीओ राजकीय टीबी अस्पताल से डॉ संदीप शुक्ला,दिशा यूनिट से दीपाली मौर्य,सीपीओ,जितेंद्र कुमार चौहान,जिला अस्पताल से, सीएचसी से एल 0 टी0, काउंसलर के पदाधिकारी, प्रताप सेवा समिति टी0आई0 परियोजना अयोध्या टीम एस0एस0के0, टीम के द्वारा शिविर का शुभारम्भ किया।शिविर मे 311 परिवहन निगम के चालक,परिचालक व कर्मचारियों ने स्वास्थ्य जांच कराया गया।उन्हें विभिन्न संक्रामक रोगों के प्रति जागरूक करना तथा समय पर जांच एवं अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों को नियमित स्वास्थ्य जांच एवं स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया गया।शिविर में परिवहन निगम के चालक, परिचालक एवं कर्मचारियों को निम्नलिखित स्वास्थ्य

सेवाएं प्रदान की गईं।शिविर मे एचआईवी एवं सिफलिस की जांच एवं परामर्श,एसटीआई जांच एवं परामर्श, टीबी (क्षय रोग) जांच एवं परामर्श,हेपेटाइटिस बी एवं सी की जांच एवं सामान्य स्वास्थ्य परामर्श सभी जांच निर्धारित काउंटरों पर व्यवस्थित एवं गोपनीय तरीके से की गईं।शिविर के सफल आयोजन में विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं की टीमों का सराहनीय योगदान रहा स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम में बड़ी संख्या में परिवहन निगम कर्मचारियों ने भाग लिया। कर्मचारियों को एक ही स्थान पर विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गईं जिससे समय की बचत के साथ–साथ रोगों की प्रारंभिक पहचान संभव हुई।स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा दी गई जानकारी से कर्मचारियों में एचआईवी, टीबी, एसटीआई एवं हेपेटाइटिस जैसे रोगों के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई।

धर्मांतरण एवं लव जिहाद के विरोध मे लखनऊ मेडिकल कॉलेज में निकला कैंडल मार्च

(राजन तिवारी संवाददाता अयोध्या धाम)

अयोध्या।धर्मांतरण एवं लव जिहाद जैसे गंभीर सामाजिक विषयों के विरोध में नेशनल मेडिकोज अग्न्याएजेश अवध प्रांत की लखनऊ महानगर इकाई ने लखनऊ मेडिकल कॉलेज परिसर में आयोजित कैंडल मार्च एवं शांतिपूर्ण प्रदर्शन समाज की सजगता और उत्तरदायित्व का सशक्त उदाहरण बना।यह आयोजन केवल विरोध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक स्पष्ट और ठोस मांग के साथ प्रशासन व सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास था।इस कैंडल मार्च का नेतृत्व भारतीय केसरिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव ने किया।उन्होंने अपने संगठन की ओर से इस प्रदर्शन का पूर्ण समर्थन करते हुए कहा कि चिकित्सा जैसे पवित्र और मानव सेवा के क्षेत्र से जुड़े किसी भी व्यक्ति द्वारा यदि लव जिहाद या धर्मांतरण जैसे कृत्यों में संलिप्तता पाई जाती है, तो वह न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि समाज और पेशे की मर्यादा के भी विरुद्ध है।प्रदर्शन के दौरान यह स्पष्ट मांग की गई कि लखनऊ मेडिकल कॉलेज में लव जिहाद एवं धर्मांतरण में संलिप्त पाए गए संबंधित डॉक्टर की मेडिकल डिग्री तत्काल समाप्त की जाए तथा उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।वक्ताओं ने कहा कि यदि ऐसे मामलों में कठोर उदाहरण प्रस्तुत नहीं किए गए, तो समाज में गलत संदेश जाएगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना कठिन हो जाएगा।कैंडल मार्च के माध्यम से उपस्थित नागरिकों, सामाजिक संगठनों और कार्यकर्ताओं ने यह संदेश दिया कि चिकित्सा संस्थान केवल इलाज का केंद्र नहीं, बल्कि नैतिकता, विश्वास और मानवता के प्रतीक होते हैं। यदि इन्हीं संस्थानों में विश्वासघात होगा, तो समाज की नींव कमजोर होगी।हाथों में जलती मोमबत्तियाँ यह प्रतीक थीं कि यह संघर्ष नफरत का नहीं, बल्कि जागरूकता, न्याय और सत्य का है।मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि भारतीय केसरिया वाहिनी सदैव समाज की बेटियों की सुरक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता और कानून के सम्मान के पक्ष में खड़ी रहेगी।उन्होंने प्रशासन से मांग की कि ऐसे मामलों में त्वरित जांच, निष्पक्ष कार्रवाई और कठोर दंड सुनिश्चित किया जाए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति अपने पद और पेशे का दुरुपयोग करने का साहस न कर सके।लखनऊ मेडिकल कॉलेज में हुआ ।

संक्षिप्त खबरें

उत्तर प्रदेश विधानसभा में औद्योगिक विकास मंत्री नन्दी ने पेश किया

लखनऊ, (संवाददाता)।उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने सदन में उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम 2025 प्रस्तुत किया। मंत्री ने सदन को जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने निवेश और औद्योगिक विकास को हमेशा प्राथमिकता दी है और समय–समय पर ठोस निर्णयों के माध्यम से अपेक्षित परिणाम प्राप्त किए हैं।मंत्री नन्दी ने बताया कि यह अधिनियम प्रदेश में औद्योगिक विकास और निवेश प्रोत्साहन के लिए ऐतिहासिक कदम है। इसके माध्यम से व्यापारियों और निवेशकों का भरोसा और विश्वास मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा 2023 में पारित जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत 42 केंद्रीय अधिनियमों में मामूली त्रुटियों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया, उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी राज्य स्तर पर मामूली चूक और दस्तावेजी त्रुटियों को गैर–आपराधिक बनाकर प्रशासन को न्यायसंगत, व्यवहारिक और सुगम बनाया है।उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम 2025 के तहत अब कारावास का प्रावधान केवल उन अपराधों के लिए रहेगा, जो शारीरिक क्षति पहुँचाते हैं या जीवन को संकट में डालते हैं। अन्य अपराधों के लिए केवल आर्थिक दंड का प्रावधान रहेगा।इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सूची के दस प्रमुख अधिनियमों में सुधार किया गया है, ।

उत्तर प्रदेश में बुनकरों की समस्याओं और सुझावों पर मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित

लखनऊ, (संवाददाता)। अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम चुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना के अंतर्गत आ रही समस्याओं और उनके निराकरण के संबंध में आज खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के सभागार में अपरान्ह 2 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग के मंत्री राकेश सचान ने की।बैठक में स्टांप तथा पंजीयन मंत्री रविन्द्र जायसवाल, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी, विधायक रफीक अंसारी, प्रमुख सचिव हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग अनिल कुमार सागर, प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड पंकज कुमार, निदेशालय एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रदेश के विभिन्न पावरलूम बुनकर बहुल क्षेत्रों के बुनकर प्रतिनिधियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया।बैठक के दौरान विशेष रूप से वाराणसी, मऊ, गोरखपुर और मेरठ परिक्षेत्र के बुनकर प्रतिनिधियों ने योजना के क्रियान्वयन में आ रही व्यवहारिक समस्याओं को साझा किया और उनके समाधान के लिए ठोस सुझाव प्रस्तुत किए। बुनकरों ने विद्युत फ्लैट रेट योजना के तहत आने वाली कठिनाइयों को विस्तार से बताया और शीघ्र निराकरण की अपेक्षा व्यक्त की।मंत्री राकेश सचान ने बुनकर प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि उनकी सभी समस्याओं एवं सुझावों को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया जाएगा और बुनकर हित में उनका व्यावहारिक समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बुनकरों के कल्याण, उत्पादन वृद्धि और रोजगार सृजन के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है और योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

विधानसभा में उठा एमओसीएच का मामला, मांग–दो विभागों में रखने के बजाय एक विभाग में रखा जाए

लखनऊ, (संवाददाता)। प्रदेश में चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य (एमओसीएच) का मामला सोमवार को विधानसभा में उठा।

मांग की गई कि एमओसीएच को दो विभागों में रखने के बजाय एक विभाग में रखा जाए और इन्हें अन्य चिकित्सकों की तरह ही पदोन्नति भी दिया जाए। मालूम हो कि अमर उजाला ने सिलसिलेवार खबरें प्रकाशित करके बताया था कि एमओसीएच की नियुक्ति आयुष विभाग में होती है, लेकिन वे काम स्वास्थ्य विभाग के अधीन करते हैं। ये जिस पद पर भर्ती होते हैं। करीब 30 साल की सेवा के बाद उसी पद से सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। आयुष एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन होने की वजह से इनकी जिम्मेदारी दोनों विभाग एक दूसरे पर टालते रहते हैं। एमओसीएच को स्वास्थ्य विभाग के अधीन करने के लिए कई बार आदेश भी हुए, लेकिन नतीजा नहीं निकला। इन खबरों को लेकर सपा विधायक डा. आरके वर्मा ने सोमवार को सदन में सवाल किया। उन्होंने पूछा कि प्रदेश में कार्यरत एमओसीएच के साथ अन्याय क्यो किया जा रहा है? क्या सरकार के पास इनके लिए कोई नीति है। ये भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। समान कार्य के बाद भी इनके साथ दुर्भावना क्यों रखी जा रही है। स्थानंतरण में भी इनके साथ भेदभाव किया जाता है।

लखनऊ में राज्य युवा उत्सव 2025–26 का भव्य उद्घाटन, युवा प्रतिभाओं ने दिखाई अपनी कला और नवोन्मेषी क्षमता

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग द्वारा आयोजित राज्य युवा उत्सव 2025–26 का उद्घाटन 22 दिसंबर, 2025 को इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमती नगर, लखनऊ में भव्य तरीके से किया गया। यह आयोजन प्रत्येक वर्ष जनपद स्तरीय और मण्डल स्तरीय युवा उत्सवों के उपरान्त आयोजित किया जाता है और यह युवा प्रतिभाओं को अपनी कला प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है।इस वर्ष राज्य युवा उत्सव में कल्चरल ट्रैक के अंतर्गत लोकगीत और लोकनृत्य की समूह प्रस्तुतियाँ तथा जीवन कौशल श्रेणी में कहानी लेखन, कविता, डिक्लेमेशन और पेंटिंग जैसी प्रतियोगिताएँ आयोजित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त इनोवेशन ट्रैक के अंतर्गत साइंस मेला (विज्ञान प्रदर्शनी) का आयोजन भी किया गया है, जिसमें प्रतिभागी युवाओं द्वारा बनाए गए मॉडल्स और नवोन्मेषी विचारों का प्रदर्शन किया गया।उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), युवा कल्याण एवं खेल, उत्तर प्रदेश गिरीश चन्द्र यादव रहे। समारोह का स्वागत सचिवध महानिदेशक युवा कल्याण सुहास एल. वाई. ने पुष्पगुच्छ देकर किया। इसके अतिरिक्त संयुक्त निदेशक अशोक कुमार कनौजिया और उप निदेशक आदित्य कुमार ने भी मुख्य अतिथि और अन्य अधिकारियों का स्वागत किया।मुख्य अतिथि गिरीश चन्द्र यादव ने समारोह के दौरान कहा कि युवा उत्सव प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने युवाओं को लगातार प्रयास करने, अपनी कला में सुधार करने और आगामी राष्ट्रीय युवा उत्सव में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने सभी प्रतिभागियों के शानदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए चयनित युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त कर प्रदेश का गौरव बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित किया।कार्यक्रम में युवाओं द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद मुख्य अतिथि ने साईंस मेला का उद्घाटन फीता काटकर किया। इस अवसर पर विज्ञान मेला में प्रस्तुत नवोन्मेषी मॉडल्स और परियोजनाओं की विशेष सराहना की गई। राज्य युवा उत्सव 2025–26 का यह आयोजन युवा प्रतिभाओं के लिए सीखने, प्रेरित होने और अपनी कला तथा नवोन्मेषी क्षमता को प्रदर्शित करने का अनूठा अवसर साबित हो रहा है।

वंदेमातरम और महंगी बिजली पर कांग्रेस का भाजपा पर हमला, आराधना मिश्रा मोना ने उठाए सवाल

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस विधानमंडल दल नेता आराधना मिश्रा मोना ने भाजपा और योगी आदित्यनाथ सरकार को वंदेमातरम के नाम पर राजनीति करने और बिजली विभाग में स्मार्ट मीटर के माध्यम से जनता को महंगी बिजली बेचने के लिए घेरा। मोना ने कहा कि वंदेमातरम देश की आजादी का प्रतीक है और इसका भावनात्मक जुड़ाव हर नागरिक से है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस का इससे कोई ऐतिहासिक संबंध नहीं है, लेकिन आज वे वंदेमातरम के नाम पर समाज में विभाजन पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वंदेमातरम गीत पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में 28 अक्टूबर 1937 को गाया

गया था और इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। उन्होंने प्रधानमंत्री और भाजपा पर दोहरी मानसिकता का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले 1998 में अटल बिहारी वाजपेई की सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश में इसे अनिवार्य करने के बाद विरोध के चलते अधिनियम समाप्त करना पड़ा था।सत्र के दौरान आराधना मिश्रा मोना ने बिजली विभाग में स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता के साथ हो रही मनमानी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर के लिए वसूली की गई कीमत का विद्युत नियामक आयोग द्वारा कोई अनुमोदन नहीं लिया गया और उपभोक्ताओं की सहमति के बिना उन्हें महंगी बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।

उन्होंने कहा कि यह गरीब, विशेषकर दिहाड़ी मजदूरों के लिए असुविधाजनक और जनविरोधी है। इसके अलावा उन्होंने 2018 में 2ळ मीटर लगाने में हुए 959 करोड़ रुपए के खर्च का हवाला देते हुए कहा कि अब वही मीटर हटाकर 681 करोड़ रुपए के स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिसका बोझ जनता पर डाला जा रहा है।आराधना मिश्रा मोना ने स्पष्ट किया कि भाजपा सरकार की यह नीति केवल प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने और बिजली को निजीकरण की दिशा में ले जाने वाली है, जबकि आम जनता और गरीब तबके की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने सदन में सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि उपभोक्ताओं के अधिकारों और हितों की रक्षा करना अपरिहार्य है।इस दौरान कांग्रेस नेता ने जोर देकर कहा कि वंदेमातरम, संविधान और बिजली जैसी जनहितकारी चीजों के नाम पर राजनीति करना जनता को गुमराह करना है और भाजपा की यह नीतियाँ लोगों के भरोसे और अधिकारों के खिलाफ हैं।

अयोध्या के लिए 25 को निकाली जाएगी पदयात्रा

लखनऊ, (संवाददाता)। चिनहट स्थित छोहरिया माता मंदिर से 25 दिसंबर को तृतीय पांच दिवसीय सनातन पद यात्रा निकाली जाएगी। इसका उद्देश्य लोगों को हिंदू संस्कृति के प्रति जागरूक करना है। सोमवार को यह जानकारी मंदिर के मुख्य पुजारी लल्ला बाबा ने दी। उन्होंने बताया कि यात्रा सुबह आठ अयोध्या के लिए प्रस्थान करेगी। रास्ते में लोगों को जागरूक करेंगे। 25 की रात्रि विश्राम सफदरगंज बाराबंकी में होगा। 26 को रात्रि विश्राम रुदौली अयोध्या में किया जाएगा। 27 को रात्रि विश्राम दिगंबरपुर अयोध्या में होगा। 28 दिसंबर को रात्रि विश्राम नेपाली बाबा आश्रम बालू घाट पर किया जाएगा। पैदल यात्रा में जगह–जगह जलपान की व्यवस्था की गई है।

30 दिसंबर को रुदौली ब्लॉक परिसर मे दिव्यांग जनों के लिए लगेगा शिविर - डीएम

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।डीएम निखिल टीकाराम फुंडे ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित मोटराईज्ड ट्राईसाईकिल योजनान्तर्गत एवं विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं से संबंधित शिविर का आयोजन 30 दिसम्बर को विकास खण्ड रुदौली परिसर में किया जायेगा।बताया कि जिन दिव्यांगजन जिनके द्वारा अभी तक मोटराईज्ड ट्राईसाईकिल योजना से लाभान्वित नहीं किया गया हो एवं उनकी दिव्यांगता का प्रतिशत कम से कम 80 प्रतिशत हो वे दिव्यांग चिन्हांकन शिविर में उपस्थित होकर अपना रजिस्ट्रेशन वांछित प्रपत्रों (आधार कार्ड, दिव्यांग प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, निवास प्रमाण–पत्र, दिव्यांगता प्रदर्शित फोटोग्राफ) के साथ उपस्थित होकर करा सकते है।बताया कि शिविरों के सफलतापूर्ण आयोजन हेतु सीएमओ डाक्टर सुशील कुमार को शिविर में आने वाले दिव्यांगजनों के उपकरण हेतु आवेदनों पर सरकारी चिकित्सक की संस्तुति हेत शिविर स्थल पर चिकित्सकों की ड्यूटी लगाना सुनिश्चित करेगे।एसडीएम रुदौली पात्र दिव्यांगजनों के आय, जाति, निवास आदि सम्बन्धी प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करेंगे।खण्ड विकास अधिकारी, रुदौली शिविर स्थल पर दिव्यांगजनों के आनलाईन आवेदन कराये जाने हेतु 01 कम्प्यूटर आपरेटर (डेस्कटाप ६ लैपटाप सहित) का प्रबन्ध करेंगे।बताया कि शिविर में आने वाले दिव्यांगजनों हेतु बैठने, ठंड से बचाव हेतु अलाव आदि की व्यवस्था करेगे।जिला समाज कल्याण अधिकारी शिविर स्थल पर सहायक विकास अधिकारी (स०क०) के माध्यम से योजनाओं से वंचित दिव्यांगजनों को शिविर स्थल पर लाये जाने हेतु प्रेरित करने तथा शिविर के दिन उन्हें स्थल पर उपस्थित रहने हेतु अपने स्तर से निर्देश प्रदान करें। जिला कार्यकम अधिकारी, अयोध्या अपने अधीनस्थ फील्ड स्टाफ के माध्यम से योजनाओं से वंचित दिव्यांगजनों को शिविर स्थल पर लाये जाने हेतु निर्देश प्रदान करेंगें।वही जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी चन्द्रेश त्रिपाठी चिन्हांकन शिविर को सफल बनाये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना सुनिश्चित करेंगें।जिससे संबंधित और अधिक जानकारी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय से संपर्क कर की जा सकती है।

जौनपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए अनंतिम मतदाता सूची जारी

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर ,24 दिसंबर। यूपी के जौनपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए अनंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। इस पुनरीक्षण अभियान के तहत जिले में 6 लाख 79 हजार 759 नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं, जबकि 5 लाख 75 हजार 889 नाम सूची से हटाए गए हैं। वर्ष 2021 की मतदाता सूची की तुलना में, 2025 के पुनरीक्षण अभियान में कुल 1 लाख 3 हजार 870 मतदाताओं की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, 64 हजार 841 मतदाताओं के नामों में संशोधन किया गया है। इस संबंध में बुधवार को जानकारी लेने पर पंचायत चुनाव अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि यह अनंतिम सूची 23 दिसंबर को प्रकाशित की गई थी। मतदाता 23 से 30 दिसंबर 2025 तक बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) और एसडीएम (उप–जिलाधिकारी) स्तर पर दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। इन दावों और आपत्तियों के निस्तारण के बाद, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 फरवरी को किया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत की निर्वाचक नामावली के लिए दो महीने से अधिक समय तक वृहद पुनरीक्षण अभियान चलाया गया। वर्ष 2021 में कुल मतदाताओं की संख्या 36 लाख 20 हजार 18 थी, जो अब अनंतिम सूची में बढ़कर 37 लाख 23 हजार 888 हो गई है। इसमें 19 लाख 66 हजार 213 महिला मतदाता और 17 लाख 57 हजार 675 पुरुष मतदाता शामिल हैं। विभिन्न ब्लॉकों की अनंतिम मतदाता सूची के अनुसार, धर्मापुर में 82,862, बदलापुर में 1,89,954, रामपुर में 1,81,102, मुफ्तीगंज में 1,21,902, जलालपुर में 1,59,281, डोभी में 1,55,526, सिकरारा में 1,64,399, महराजगंज में 1,56,386, मड़ियाहूं में 1,96,901, सुजानगंज में 2,10,668, केराकत में 1,67,025, सुइथाकला में 1,76,647, सिरकोनी में 1,46,942, खुटहन में 2,05,931, बरसठी में 1,92,128, रामनगर में 1,94,255, बक्शा में 1,78,609, करंजाकला में 1,95,844, मछलीशहर में 2,05,595, मुंगराबादशाहपुर में 1,64,275 और शाहगंज में 2,77,656 मतदाता दर्ज किए गए हैं।

संक्षिप्त खबरें

जौनपुर में प्रदेश स्तरीय महिला वॉलीबॉल, खो–खो 25 से 27 दिसंबर तक होगा आयोजन

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,24 दिसंबर। यूपी के जौनपुर में खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा प्रदेश स्तरीय महिला वॉलीबॉल और खो–खो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर 25 से 27 दिसंबर, 2025 तक इन्दिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम, सिद्दीकपुर में होगी।इस संबंध में बुधवार को जानकारी देते हुए जिला क्रीड़ा अधिकारी चंदन राय ने बताया कि इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 18 मंडलों से दो–दो टीमें हिस्सा लेंगी, जिससे कुल 36 टीमें प्रतिभाग करेंगी। खेल सुबह 9 बजे से शाम तक आयोजित किए जाएंगे। खिलाड़ी टीमों के ठहरने की व्यवस्था वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर स्थित ज्योतिबा फूले और बाबू जगजीवन राम छात्रावास में की गई है। प्रतियोगिता स्थल से पूर्वांचल विश्वविद्यालय तक टीमों के आने–जाने के लिए बस की व्यवस्था भी की गई है। निर्णायकों और अधिकारियों के ठहरने का इंतजाम भी विश्वविद्यालय परिसर में ही किया गया है। प्रतियोगिता का उद्घाटन 25 दिसंबर, 2025 को उत्तर प्रदेश शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरीश चंद्र यादव द्वारा किया जाएगा। समापन समारोह और पुरस्कार वितरण 27 दिसंबर, 2025 को होगा। यह आयोजन जिला प्रशासन के सहयोग से संपन्न कराया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा डॉक्टरों और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, जबकि पुलिस विभाग ने महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिसकर्मियों को तैनात किया है।

महापौर व नगर आयुक्त के मुताबिक राम नगरी मे 27 से होगा प्रदेश भर के महापौर का जमावड़ा

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।निरंतर नवाचार में जुटे अयोध्या नगर निगम ने व्हाट्सएप के माध्यम से उपभोक्ताओं को गृह–जल एवं सीवर कर का बिल पहुंचाने एवं भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है।बुधवार को तिलक हाल में आयोजित पत्रकार वार्ता में नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार एवं पार्षदों की मौजूदगी में उन्होंने लैपटॉप पर बटन दबाकर इस सेवा का शुभारंभ किया।उन्होंने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा के माध्यम से शुरू की गई सेवा में सभी प्रकार की संपत्ति कर जमा करने की सुविधा उपभोक्ताओं को हासिल हो गई है। उन्हें रसीद भी व्हाट्सएप पर ही सुलभ करा दी जाएगी। इससे किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की आशंका नगण्य हो जाएगी।उन्होंने बताया कि आगामी 27 एवं 28 दिसंबर को प्रदेश भर के सभी 17 महापौर अयोध्या आएंगे। वह पंचशील होटल में आयोजित सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वे अयोध्या में किए जा रहे पार्किंग, पार्कों के सुंदरीकरण, स्वच्छता, पेयजल

समेत विभिन्न व्यवस्था के नवाचारों से परिचित होंगे और अपने नवाचारों से अयोध्या के पार्षद दल तथा अधिकारियों को परिचित कराएंगे।नगर आयुक्त ने बताया कि बैंक ऑफ बरोदा के सहयोग से व्हाट्सएप के माध्यम से शुरू होने वाली कर वसूली की सुविधा से लोगों को काफी आसानी होगी और नगर निगम में मानव संसाधनों की बचत होगी। उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि नगर निगम की आमदनी बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र को भी आमंत्रित किया गया है।आगामी 27 दिसंबर से शुरू होने वाले दो दिवसीय महापौर सम्मेलन के लिए आयोजन समिति का गठन किया गया है, जिसमें 12 पार्षद शामिल हैं।

नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश पांडेय ने बताया कि सदस्यों में पार्षद अनुज दास, विशाल पाल, संतोष सिंह, अनिल सिंह, विश्वजीत, विनय जायसवाल, मनीष यादव निखिल, राजकरन, अर्चना श्रीवास्तव, सुमन यादव, सलमान हैदर, बृजेंद्र सिंह शामिल हैं। सलमान हैदर को मीडिया की जिम्मेदारी सौंप गई है।इस मौके पर अपर नगर आयुक्त डॉ. नागेंद्र नाथ एवं भारत भार्गव, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी गजेंद्र कुमार के अलावा पूर्व उप सभापति जयनारायण सिंह रिंकू, पार्षद अनुज दास, अनिल सिंह, बृजेंद्र सिंह, दीप गुप्ता, चंदन सिंह, संतोष सिंह, विकास पाल, धर्मेंद्र मिश्र, सूर्यकुमार तिवारी सूर्या आदि मौजूद थे।

महिलाओं और बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अतुल्य वेल्फेयर ट्रस्ट ने एक महीने निशुल्क सौंदर्य प्रशिक्षण कार्यशाला का किया शुभारंभ

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर।अतुल्य वेल्फेयर ट्रस्ट ने युवतियों और महिलाओ को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पुनः निःशुल्क एक माह ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन निखार ब्यूटी पार्लर खुझी मोड हिसामपुर रोड डोभी में किया! कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए मुख्य अतिथि प्रो सरिता सिंह श्री गणेश राय पी जी कालेज डोभी ने कहा कि अतुल्य वेल्फेयर ट्रस्ट द्वारा नारी उत्थान एवम उनकी आत्मनिर्भरता के लिए इस तरह के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन निश्चित रूप से प्रशिक्षणार्थियों के लिए कारगर साबित होगा, संस्थाध्यक्ष उर्वशी सिँह ने प्रशिक्षिका श्रीमती सरोज गुप्ता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि महिलाओ को स्वावलंबी बनाने की इस मुहिम से युवतियां अपने पैरों पर खड़ी हो सकेंगी तथा उनके आत्मविश्वास मे वृद्धि होगी! ट्रस्ट परिवार द्वारा इस तरह के कई बार प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा चुका है, कार्यक्रम में बच्चियों का उत्साह देखकर बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है,! बड़ी संख्या में बच्चियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया! प्रशिक्षिका सरोज गुप्ता ने कहा कि बच्चियों को सिखाने के बाद हर सप्ताह एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा जिसमें बेहतर प्रदर्शन करने पर समापन समारोह में सम्मानित किया जाएगा!जिससे बच्चियों के अंदर सीखने की चाह और उत्साह की भावना बनी रहेगी! कार्यक्रम में मुख्य रूप से ट्रस्ट परिवार के तरफ से सदस्य , और, धरमू गुप्ता, शहजादी गुप्ता, दिनेश, उपेन्द्र, ट्रेनर डिम्पल, खुशी, अन्य लोग उपस्थित रहे, कार्यक्रम का संचालन और आभार संस्था समाजसेवा अध्यक्ष मीरा अग्रहरी ने किया।

अरावली बचाओ–भविष्य बचाओ" के नारे के साथ ब्रेकथ्रू साइंस सोसाइटी का प्रदर्शन

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। यूपी के जौनपुर में अरावली पर्वत श्रृंखला और पर्यावरण पर बढ़ते खतरे को लेकर विज्ञान संगठन ब्रेकथ्रू साइंस सोसाइटी के तत्वावधान में बुधवार को बदलापुर के इंदिरा चौक पर पोस्टर प्रदर्शन आयोजित किया गया। इससे पूर्व बरौली (सुल्तानपुर रोड) से इंदिरा चौक तक सैकड़ों छात्र–छात्राओं ने "अरावली बचाओदृभविष्य बचाओ" के नारे लगाते हुए जुलूस निकाला। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ब्रेकथ्रू साइंस सोसाइटी की श्रीमती अंकिता मौर्य ने कहा कि उद्योगपतियों के स्वार्थ में वनभूमि, जल निकायों, पहाड़ियों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर विनाश गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पर्यावरण मंत्रालय की एक सिफारिश स्वीकार करते हुए अरावली में केवल 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भू–आकृतियों को अरावली पहाड़ियों की श्रेणी में रखने का निर्णय लिया गया है, जिससे पूरी पर्वत श्रृंखला के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। इससे खनन माफियाओं और अतिक्रमणकारियों के लिए रास्ता खुल सकता है। उन्होंने कहा कि गुजरात से हरियाणा और दिल्ली तक लगभग 700 किलोमीटर में फैली अरावली पर्वतमाला न केवल विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, बल्कि समृद्ध जैव विविधता का केंद्र और उत्तरी भारत के पर्यावरण संतुलन की रीढ़ भी है। अवैध खनन, रियल एस्टेट अतिक्रमण और अविवेकपूर्ण विकास योजनाओं के कारण यह क्षेत्र पहले ही गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि पारिस्थितिकी तंत्र को केवल संख्याओं के आधार पर आंकना एक खतरनाक प्रवृत्ति है। आज बढ़ता प्रदूषण, अनिश्चित मौसम, बार–बार आने वाली प्राकृतिक आपदाएं, आदिवासी क्षेत्रों का सिमटना, हिमालय की अस्थिरता और नदियों का विनाश इसी सोच का परिणाम है, जो कॉर्पोरेट मुनाफे के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह सकारात्मक संकेत है कि अब लाखों आम लोग अरावली की रक्षा के लिए आगे आ रहे हैं। इस अवसर पर अंकित, आशीष, रईस, जितेंद्र, शनि, कोमल, नेहा, किरण, संतोष, अजय, राज सहित बड़ी संख्या में छात्र–छात्राएं उपस्थित रहे।

संक्षिप्त खबरें

मुख्यमंत्री दरबार पहुंचा निर्मला अस्पताल का मामला

अयोध्या। पिछले दिनों निर्मला हॉस्पिटल में सरोज की इंजेक्शन के ओवरडोज से मौत हो जाने के मामले में पीड़ित पक्ष ने मुख्यमंत्री से शिकायत की है।सरोज का पुत्र 20 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जनता दरबार में मिलने गोरखपुर गया था। मुख्यमंत्री ने पीड़ित को कार्रवाई का भरोसा दिया है। सुशील ने सीएम को शिकायती पत्र भी दिया, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि निर्मला हॉस्पिटल में उसकी मां का इलाज चल रहा था। डिस्चार्ज वाले दिन डॉ. आरके बनौधा के लिखे इंजेक्शन के ओवरडोज के कारण उसकी मां की तबीयत बिगड़ गई। लखनऊ रेफर कराया, लेकिन वहां के डॉक्टरों के भरसक प्रयास के बाद भी उनकी मृत्यु हो गई। डॉ. बनौधा ने गलती स्वीकारते हुए लिखित कबूलनामा भी दिया है।उसने सीएम से मांग की है कि दोषी चिकित्सक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए और अस्पताल का लाइसेंसध्पंजीकरण निलंबित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

69 वें नेशनल स्कूल गेम्स खो खो अंडर 17 बश्रयज एंड गर्ल्स टूर्नामेंट 2025 मे भोजन व अन्य व्यवस्था की कोच व खिलाडियों ने की सराहना

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।20 दिसंबर से 24 दिसंबर तक शहर के जीआईसी मैदान पर 69 वें नेशनल स्कूल गेम्स खो खो अंडर 17 बॉयज एंड गर्ल्स टूर्नामेंट 2025 संयुक्त शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) योगेंद्र सिंह,सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक के साथ–साथ जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ पवन कुमार तिवारी,सह जिला विद्यालय निरीक्षक अवनीश कुमार पाण्डेय की देखरेख में चला।इस टूर्नामेंट में देश के कई प्रदेशों से खिलाड़ी आए हुए हैं।शिक्षा विभाग द्वारा इन खिलाड़ियों तथा कोच को किसी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए आयोजक द्वारा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को अलग–अलग जिम्मेदारी सौंप गई है।परिवहन, ठहराने व खान–पान की व्यवस्था के लिए भी शिक्षा अधिकारियों तथा कर्मियों को जिम्मेदारी सौंप गई है।भोजन संबंधी जिम्मेदारी सह जिला विद्यालय निरीक्षक अयोध्या अवनीश कुमार पांडे को सौंपी गई है।उनकी इस व्यवस्था से प्रतियोगिता में आये खिलाड़ियों तथा कोच ने भोजन के साथ–साथ नाश्ते की जमकर तारीफ किया।बताया कि विभाग द्वारा भोजन व नाश्ते की व्यवस्था अति सराहनीय है।यहां पर 'ड्यूटी में लगे माध्यमिक शिक्षक संघ (शर्मा गुट) उत्तर प्रदेश ड्यूटी महानगर अध्यक्ष अनूप पांडे, महानगर मंत्री महानगर मंत्री सत्य प्रकाश, डॉ प्रतिभा पाठक, सत्येंद्र त्रिपाठी सहित अन्य कर्मी सह जिला विद्यालय निरीक्षक अवनीश कुमार पांडे के निर्देश पर भ्रमण करते हुए दिखाई दिए इस दौरान उन्होंने स्टालों पर लगे भोजन,नास्ता आदि को चेक किया। बल्कि यहां पर मौजूद विभिन्न प्रांतो से आए खिलाड़ियों से भी भोजन के बारे में पूछा जहां पर उनको संतोषजनक उत्तर प्राप्त हुआ।

अंतरराष्ट्रीय मैत्री का प्रतीक बनी महारानी हो मेमोरियल पार्क, महापौर ने किया प्रतिमा का अनावरण

(राजन तिवारी संवाददाता अयोध्या धाम)

अयोध्या।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में रामनगरी अयोध्या को वैश्विक सांस्कृतिक पहचान दिलाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बुधवार को देखने को मिला।बुधवार को सरयू तट से सटे क्वीन हो मेमोरियल पार्क में अयोध्या की राजकुमारी एवं दक्षिण कोरिया की महारानी हो (क्वीन हो) की भव्य कांस्य प्रतिमा का विधिवत अनावरण महापौर गिरीश पति त्रिपाठी द्वारा किया गया।यह ऐतिहासिक अवसर भारत और कोरिया गणराज्य के बीच लगभग 2000 वर्ष पुराने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करने वाला है। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ हुई। इसके पश्चात विधिविधान से महारानी हो की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसने उपस्थित जनसमूह को भावनात्मक रूप से जोड़ दिया।इस अवसर पर महापौर गिरीश पति त्रिपाठी ने कहा कि आज का दिन भारत और कोरिया गणराज्य के अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक नया और विशेष आयाम जोड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि अयोध्या की वह राजकुमारी, जो लगभग 2000 वर्ष पूर्व समुद्री मार्ग से कोरिया गईं थीं, वहां के कांस्य वंश की जननी मानी जाती हैं। आज भी दक्षिण कोरिया में उनका गहरा सम्मान और व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है।महापौर ने कहा कि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतदृकोरिया के इन ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों को समय रहते पहचानते हुए सरयू तट पर क्वीन हो मेमोरियल पार्क का निर्माण कराया। उसी क्रम में महारानी हो की प्रतिमा की स्थापना हम सभी के लिए गर्व, श्रद्धा और शुभ अवसर का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हम अपने उस पूर्वज को श्रद्धा के साथ स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने अयोध्या से कोरिया जाकर दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच सेतु का कार्य किया।पार्क की चीफ कोऑर्डिनेटर वंदना शर्मा ने बताया कि क्वीन हो मेमोरियल पार्क अयोध्या और कोरिया के ऐतिहासिक रिश्तों का प्रतीक स्थल है। महारानी हो अयोध्या की राजकुमारी थीं, जो लगभग 2000 वर्ष पूर्व समुद्री मार्ग से कोरिया गईं और वहां के राजा से विवाह किया। उनके माध्यम से दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों की मजबूत नींव पड़ी। उन्होंने जानकारी दी कि स्थापित की गई प्रतिमा लगभग 12 फुट ऊंची। रॉक स्टोन मटेरियल से निर्मित यह प्रतिमा अत्यंत आकर्षक ढंग से डिजाइन की गई है। इसका निर्माण कोरिया के कुशल कारीगरों द्वारा किया गया है और इसे अयोध्या तक पहुंचाने में लगभग 20 दिन का समय लगा।पार्क में आने वाले दर्शकों का गौरवशाली अतीत से साक्षात्कार हो और भावी पीढ़ी भी इतिहास से अवगत हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। पार्क में ध्यान केंद्र, प्रदर्शनी कक्ष के साथ विशाल सरोवर एवं उस पर आकर्षक सेतु का निर्माण किया गया है। सेतु के एक छोर पर राजा सूरो का किंग पवेलियन तथा दूसरे छोर पर अयोध्या का प्रतिनिधित्व करता रानी हो का क्वीन पवेलियन स्थित है। राजकुमारी श्रीरत्ना की कोरिया यात्रा की प्रतीकात्मक नाव तथा मार्ग में प्राप्त गोल्डन एग भी पार्क में स्थापित किया गया है। उल्लेखनीय है कि करीब 21 करोड़ रुपये की लागत से विकसित क्वीन हो मेमोरियल पार्क का निर्माण सितंबर 2019 में प्रारंभ हुआ था और नवंबर 2021 में इसका कार्य पूर्ण कर लिया गया था। इस पार्क का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकभवन में मार्च 2024 में किया था। पार्क में मेडिटेशन हॉल, क्वीन पवेलियन, किंग पवेलियन, वाटर टैंक, फुट ओवर ब्रिज, सब स्टेशन, ट्यूबवेल, पाथवे, शौचालय, फाउंटेन, ओपन एयर थिएटर, लैंडस्केपिंग, स्कल्प्चर, गार्ड रूम, म्यूरल, ऑडियोदृवीडियो सिस्टम, बाउंड्री वॉल, पार्किंग तथा पॉण्ड जैसी आधुनिक सुविधाओं का निर्माण किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल ने दिया चेतावनी ,पूरे देश में बांग्लादेश के विरोध में किया जाएगा आंदोलन

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल ने बुधवार को बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा और उत्पीड़न को रोकने के लिए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन कलेक्ट्रेट परिसर में सिटी मजिस्ट्रेट इंद्र नंदन सिंह को देते हुए उचित कार्रवाई का आग्रह किया गया है। संगठन के जिलाध्यक्ष अजय पांडेय ने बताया कि पिछले वर्ष बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के तख्तापलट के बाद से अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, उत्पीड़न और हत्या की लगभग 88 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इन घटनाओं में हजारों लोगों की जान जा चुकी है। पांडेय के अनुसार, बांग्लादेश में 1971 जैसे हालात बन गए हैं, जहां हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और हिंदू घरों को जलाया जा रहा है। लूटपाट और मारकाट की घटनाएं भी हो रही हैं। उन्होंने दीपू चंद दास नामक एक हिंदू युवक की हत्या का भी उल्लेख किया, जिसे मारकर पेड़ पर लटकाकर जला दिया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री के घर को भी आग के हवाले कर दिया गया है। संगठन ने दावा किया कि इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकवादी उस्मान हादी की मृत्यु के बाद ढाका में भारत विरोधी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, जिससे पूर्वोत्तर भारत पर खतरा उत्पन्न हो गया है। उनका आरोप है कि सत्ता, सेना और सरकार गृह युद्ध जैसी स्थिति के सामने लाचार दिख रहे हैं। ष्अल्ला हू अकबरष् के नारों के साथ मकानों और दुकानों में आग लगाई जा रही है, और ष्ग्रेटर बांग्लादेशष् का नक्शा बनाकर भारत की सीमाओं को चुनौती देने की तैयारी की जा रही है। अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल ने चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में उचित कदम नहीं उठाए गए, तो डॉ. प्रवीण भाई तोगड़िया के नेतृत्व में पूरे देश में बांग्लादेश के विरोध में आंदोलन किया जाएगा।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।